मुंबई(महाराष्ट्र) से प्रकाशित

उत्तरशक्ति

हिन्दी दैनिक

मुंबई
वर्षः 9 अंक 128
शुक्रवार, 20 नवम्बर 2026
मूल्य 3 रुपए, पृष्ठ-6
RNI NO. MAHHIN/2018/76092
email ID- uttarshaktinews@gmail.com
www.uttarshaktinews.com

हर खबर निष्पक्षता के साथ

टैक्स कटौती के बावजूद नौकरियों की कमी और कम सैलरी पर पीएम मोदी ने उद्योगपतियों को लगाई फटकार

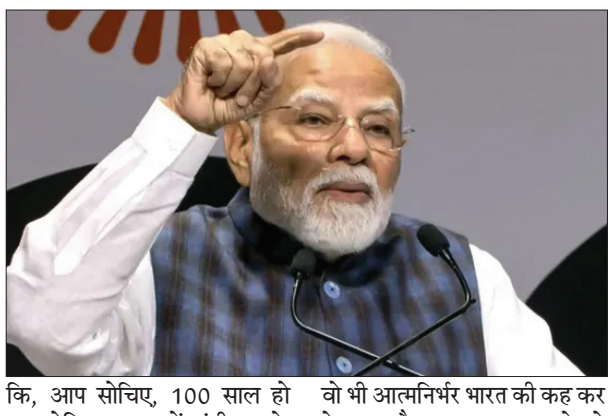
नई दिल्ली, 19 नवम्बर। नई दिल्ली के भारत मंडपम में फिक्की के सौवें सालाना अधिवेश में उपस्थित इंडिया इंक के सैकड़ों दिग्गजों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस साफगोई से अपनी बात सामने रखी और भारतीय उद्योग जगत को उनकी कमियों के बारे में अवगत कराया, उसे सरकार और कारपोरेट के बीच संवाद के नये मापदंड के तौर पर चिन्हित किया जाएगा।

पीएम मोदी ने भारतीय कंपनियों पर सीधे आरोप लगाया कि वो ना तो आत्मनिर्भर भारत के एजेंडे पर चल रहे हैं, ना ही कृषि क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं और ना ही कारपोरेट टैक्स घटाने की सहूलियत का फायदा जनता या देश को दे रहे हैं।

पीएम मोदी ने भारतीय उद्यमों को घरेलू बाजार केकाम्फोर्ट जोन से बाहर निकल कर देशवासियों को भी एक्सपोर्ट क्वालिटी की वस्तुएं व सेवाएं देने की उलाहना दी। पीएम मोदी ने आग्रह भी किया कि, बिना संकोच, बिना झिझक, मुझे खुल कर के लिख कर के भेजिए कि अभी भी क्या सुधार जरूरी हैं।

पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरूआत भारत की आर्थिक प्रगति, लगातार सात फीसद से ज्यादा की विकास दर, 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने, गुड्स निर्यात हर महीने 50 अरब डालर को पार करने जैसी उपलब्धियों से की लेकिन उसके बाद उनकी भाषा तल्ख होती गई और उद्योग जगत को उनकी एक के बाद एक खामियां गिनाई।

सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत योजना का मुद्दा उठाया और कहा



कि, आप सोचिए, 100 साल हो गए, लेकिन 1930 में गांधी आपके यहां आकर के यही कह के गए थे, और आज इतने साल के बाद भी मुझे वही कहना पड़ रहा है, यह आपकी सफलता है कि विफलता है?

मेरी मत मानो, गांधी की तो मानते भाई! वो भी स्वदेशी कह कर के गए, वो भी आत्मनिर्भर भारत की कह कर के गए, और आप 100 साल के हो गए, बात वहीं की वहीं रह गई।

इस क्रम में उन्होंने फार्मा, लौह-इस्पात जैसे उद्योगों का उदाहरण दिया जहां भारत एक बड़ा निर्यातक व उत्पादक होने के बावजूद बड़ा आयातक भी बना बैठा है। फिर उन्होंने सामने बैठे उद्योगपतियों से पूछा, आप मुझे बताइए भाई, ऐसा कैसा देश और कैसे मेरे उद्योग जगत के साथी, गेहूं तो एक्सपोर्ट करे और ब्रेड इम्पोर्ट करे! पूछिए अपने आप को। इसके बाद मोदी ने कहा कि, हमारा कारपोरेट जगत कृषि क्षेत्र में निवेश करने से डरता है, भागता है। जबकि इतना बड़ा देश होने के बावजूद भारत का वैश्विक कृषि व्यापार में सिर्फ दो-ढ़ाई फीसद हिस्सा है। इसके बाद उन्होंने ईज आफ डूइंग बिजनेस व कारपोरेट टैक्स में कमी के सरकार के फैसले को उठाया और कहा कि, 2014 में बेसिक कारपोरेट टैक्स रेट 30 फीसद होता था। हमने इसे कम कर-के 22 परसेंट तक पहुंचा दिया है। आज भारत में 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई कर नहीं है।

हाईकोर्ट के फैसले पर अभिषेक बनर्जी का हमला, न्याय सत्ताधारी दल का निजी विशेषाधिकार नहीं

कोलकता, 19 नवम्बर। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को कानूनी राहत के कथित चयनात्मक इस्तेमाल की आलोचना की। उन्होंने कहा कि न्याय सत्ताधारी दल का निजी विशेषाधिकार नहीं बनना चाहिए। उनकी यह टिप्पणी कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा उनके निजी सहायक सुमित रॉय की उस याचिका को खारिज किए जाने के बाद आई है, जिसमें उन्होंने चार आपराधिक मामलों में अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी। इन मामलों में उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार दिखाया गया है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, न्याय सत्ताधारी दल का निजी विशेषाधिकार और विपक्ष का निरंतर संघर्ष नहीं बन सकता। ऐसा लगता है कि राहत केवल भाजपा नेताओं और उनके करीबी लोगों के लिए आरक्षित है, जबकि विपक्ष को संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के लिए संघर्ष



करना पड़ रहा है। टीएमसी नेता की यह प्रतिक्रिया उच्च न्यायालय द्वारा चार मामलों में रॉय की अंतरिम सुरक्षा की मांग को खारिज करने के बाद आई है। रॉय फिलहाल सालबोनी में जमीन घोटाले के एक कथित मामले के सिलसिले में हिरासत में हैं।

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने की। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामलों में रिट कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए, खासकर तब जब पीड़ित व्यक्ति के पास कानूनी राहत के अन्य विकल्प मौजूद हों। रॉय ने चार मामलों में अंतरिम सुरक्षा पाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिनमें उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार दिखाया गया था। उनके वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ राजनीतिक कारणों से कई मामले दर्ज किए गए हैं। वकील ने यह भी कहा कि रॉय को बाकी चार मामलों में सुरक्षा की जरूरत है, जबकि वह उस मामले में कानूनी उपाय अपना रहे हैं जिसमें वे अभी हिरासत में हैं। हालांकि, अदालत ने रॉय द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान, रॉय ने अधिकारियों को उनके खिलाफ नए मामले दर्ज करने या मौजूदा मामलों में सख्त कार्रवाई करने से रोकने का आदेश भी मांगा। जस्टिस भट्टाचार्य ने इस अनुरोध को भी खारिज कर दिया।

विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करना शर्मनाक, राहुल गांधी पर किरेन रिजिजू का तीखा हमला

नई दिल्ली, 19 नवम्बर। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विदेशी धरती से भारत के लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाओं और अर्थव्यवस्था को लेकर कथित तौर पर झूठे और निराधार बयान देने का आरोप लगाया है।



शिकागो विश्वविद्यालय में भारत की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को लेकर गांधी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रिजिजू ने कहा कि वह भारत के सच्चे प्रतिनिधि की तरह नहीं, बल्कि देश विरोधी ताकतों के मोहरे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ इस तरह के आपत्तिजनक बयान देना बेहद शर्मनाक है।

उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की सोच भारत के संविधान, लोकतंत्र और परंपराओं का अपमान करने वाली हो गयी है और ऐसा प्रतीत होता है कि विदेशी भारत विरोधी ताकतें उन्हें लगातार उकसा रही हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी सच्चा भारतीय अपने देश के बारे में इस तरह की बातें नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री ने भारत की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक जैसी प्रमुख वित्तीय संस्थाएं भी भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था मानती हैं।

उन्होंने कहा कि आईएमएफ भारत की संस्था नहीं है, इसके बावजूद राहुल गांधी यह दावा कर रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। भारत की प्रगति को नकारकर राहुल गांधी वास्तव में खुद और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने देश में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राहुल गांधी की टिप्पणियों को भी खारिज किया। उन्होंने सवाल किया कि जो व्यक्ति सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सरकार की आलोचना करता है, वह किस आधार पर देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र नहीं होने की बात कहता है।

जयशंकर ने चीन-पाकिस्तान पर साधा निशाना; बोले- संसाधनों और समुद्री रास्तों को हथियार बना रहे ये देश, भारत-जापान की दोस्ती जरूरी

जापान, 19 नवम्बर। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बृहस्पतिवार को संसाधनों, संपर्क मार्गों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को "हथियार" के रूप में इस्तेमाल किए जाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई और कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत और जापान जैसी विश्वसनीय साझेदारियों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बृहस्पतिवार को तोक्यो में आयोजित भारत-जापान विदेश एवं रक्षा मंत्रियों की चौथी वार्ता में शामिल हुए, जिसे 2+2 बैठक भी कहा जाता है। वार्ता के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि वैश्विक व्यवस्था इस समय कई तरह के झटकों का सामना कर रही है, जिनमें दो बड़े जारी संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता और कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाक्रम ने ऊर्जा, व्यापार, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। जयशंकर ने कहा, "जब हम इन मोर्चों पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं, तब भारत और जापान जैसी विश्वसनीय एवं सार्थक साझेदारियां और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं।"

रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का प्रभाव संबंधित क्षेत्रों से कहीं आगे तक पड़ा है। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार, समुद्री परिवहन और खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई है। मंत्री ने कहा, "हमने संपर्क मार्गों, संसाधनों, सेवाओं, आपूर्ति श्रृंखलाओं और बाजार हिस्सेदारी को हथियार के रूप में

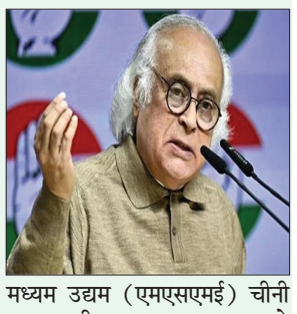


इस्तेमाल करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी चर्चा की।" उन्होंने कहा कि इनमें से कई घटनाक्रम का राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जयशंकर ने कहा, "इस संदर्भ में अपनी क्षमताओं को मजबूत करना तथा नए विकल्प तलाशना महत्वपूर्ण है।" उन्होंने खाड़ी क्षेत्र के अनुभवों के मद्देनजर संपर्क मार्गों और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को लेकर बढ़ती चिंताओं का भी उल्लेख किया और समुद्री व्यापार का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। जयशंकर ने कहा, "यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि समुद्री व्यापार सुचारू रूप से संचालित हो, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य का केंद्र है। हमारा समुद्री सहयोग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।" जयशंकर की यह टिप्पणी पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों, विशेषकर होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यापारिक जहाजों पर हो रहे हमलों के बीच आई है।

इन हमलों में कई भारतीय नाविकों की मौत हुई है। सुरक्षा संबंधी स्थिति ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्गों से होने वाले समुद्री व्यापार की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। जयशंकर ने कहा कि दोनों देश इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन के महत्व पर भी सहमत हुए। उन्होंने कहा कि वार्ता में युद्ध के बदलते स्वरूप, आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल और नवोन्मेषी समाधानों जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान बहुध्रुवीय एशिया और बहुध्रुवीय विश्व के पक्षधर हैं तथा दोनों देश बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार के प्रबल समर्थक रहे हैं। उन्होंने कहा, "भारत और जापान के बीच मजबूत संबंध निश्चित रूप से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

कांग्रेस का सरकार पर कटाक्ष: 'मेक इन इंडिया' बन गया है 'इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना'

नई दिल्ली। कांग्रेस ने चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे में कथित वृद्धि को लेकर बृहस्पतिवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा और कटाक्ष करते हुए कहा कि 'मेक इन इंडिया' अब 'इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना' बन गया है।



कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2026-27 में रिकॉर्ड 150 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की राह पर है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 112 अरब डॉलर था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता संभाली थी, तब चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा महज 36 अरब डॉलर था।

रमेश ने कहा, "मोदी ने 12 वर्षों में इसे चार गुना से अधिक बढ़ा दिया है। 'मोदी है तो मुमकिन है'। इससे भारत का विनिर्माण क्षेत्र कमजोर हो रहा है और हमारे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) चीनी आयात की बाढ़ का मुकाबला करने में असमर्थ हो रहे हैं।" उन्होंने दावा किया कि सौर विनिर्माण जैसे महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों में भारत चीन से आयातित कलपुर्जों पर पूरी तरह निर्भर है। रमेश ने कटाक्ष किया, "मेक इन इंडिया अब इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना बन गया है।" उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीनी अतिक्रमण की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार के पास न तो व्यापार के मुद्दे पर और न ही सीमा के मुद्दे पर कोई जवाब है।

2027 विधानसभा चुनाव से पहले आप को झटका, नवदीप सिंह संघा ने थामा बीजेपी का दामन

पंजाब, 19 नवम्बर। आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे नवदीप सिंह संघा अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में पार्टी की सदस्यता ली, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों मौजूद थे। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले यह एक अहम घटनाक्रम है; हाल के हफ्तों में



'आप' के कई नेता BJP में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा, BJP ने 'आप' के उन तीन विधायकों का भी स्वागत किया है जो 2 नवंबर को पार्टी में शामिल हुए थे। इनमें कुंवर विजय प्रताप सिंह, चेतन सिंह जौरामाजरा और हरमीत सिंह पठानमाजरा शामिल हैं, जिन्होंने नई दिल्ली स्थित BJP मुख्यालय में औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ली। इस कार्यक्रम में दर्शन सिंह डिम्पी, रविंदर सिंह, रविंदर रानी, रविंदर कौर रानी और तजिंदर मोनू समेत कई अन्य स्थानीय नेताओं के भी पार्टी में शामिल होने की घोषणा की गई। इनके अलावा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष विजय तिवारी और पूर्व अध्यक्ष बताए जा रहे नरेश शर्मा भी उन लोगों में शामिल थे, जिनका जिक्र किया गया। AAP के ये तीनों पूर्व विधायक पंजाब के अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। कुंवर विजय प्रताप सिंह अमृतसर उत्तर से विधायक थे, चेतन सिंह जौरामाजरा समाना का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि हरमीत सिंह पठानमाजरा पटियाला जिले के सनौर से चुने गए थे। इनके पार्टी छोड़ने से पहले, भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार के साथ इनके कई मतभेद सामने आए थे। पठानमाजरा और जौरामाजरा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया था कि वह नशीले पदार्थों की समस्या, बढ़ता कर्ज और शासन से जुड़ी चिंताओं जैसे बड़े मुद्दों को सुलझाने में विफल रही है। जौरामाजरा, जो पंजाब सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने के सरकार के तरीके पर सवाल उठाए थे।

DAKS REHAB CENTRE
(PARALYSIS PHYSIOTHERPHY CENTER AND OLD AGE HOME)
Contact us: 9820519851
विल्डिंग नंबर 3, प्लॉट नंबर 3, आदर्श घरकुल सोसायटी सायन कोलीवाडा जीटीबी नगर मुंबई-37
* Stroke/Paralysis/Complete Rehab Centre
* बाहर से आये रोगी और उनके परिजनो के ठहरने कि व्यवस्था
* वृद्ध लोगों के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध
* DM/HT/THYROID इन सब से कैसे बचें
* NGO में मिलनेवाली सहायता को लोगों में देना
* चिकिस्ता उपकरणो को किराये और बिक्री सुविधा उपलब्ध
* एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध
* पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब सेंटर
* मरीजों के लिए घर पर 12 और 24 घंटे जीडीए परिचारक
* विशेषज्ञ डॉक्टरो से ऑनलाइन और ऑफलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध
* मासिक ईएमआई के आधार पर व्यक्तीयों, परिवारो और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य निती की चिकिस्ता सुविधा उपलब्ध



TIWARI'S SARASWATI CLASSES
— Since 1992 —
Parents' First Choice for 34+ Years
Prof. Dr. Dayanand Tiwari
Founder & Academic Director
ADMISSIONS OPEN
9th | 10th | 11th | 12th SCIENCE
NEET | JEE | MHT-CET
10 DAYS FREE DEMO
Attend Classes • Experience Our Teaching
Take Admission After Satisfaction
(No Hidden Conditions)
34+ Years of Academic Excellence
Experienced & Dedicated Faculty
Personal Attention
Printed Notes & Regular Tests
Strong Foundation for Boards & Competitive Exams
Santacruz Branch
101 Sai Chambers, Opp. Santacruz Railway Station (East), Near Depot, Santacruz (E), Mumbai-400055
Sion Branch
Opp. SIES College (Old), Near Gurukripa Hotel, Sion (West), Mumbai
Limited Seats / Small Batch Size
CALL NOW:
7738007373

NEW LIGHT CLASSES
TRADITION OF EXCELLENCE
2nd Floor, Sheetal Bldg. Near Diamond Talkies, L. T. Road, Borivali (West) Mumbai - 400 092 Maharashtra
ADMISSIONS OPEN
ALL OVER INDIA
ENROLL NOW



SMART CLASSROOM
(ONLINE/OFFLINE)
Courses Offered
Std. XI & XII (Sci.)
NEET
JEE (Main & Advance)
MHT-CET
Polytechnic & Engg
Physics and Maths (ICSE, CBSE, ISC)
M: 9833240148 | E: edu@newlightclasses.com | W: www.newlightclasses.com

विश्व बाल दिवस–20 नवम्बर 2026

हिंसा, शोषण और अभाव से मुक्त हो भारत का बचपन



-ललित गर्ग

हम में से प्रत्येक को बच्चों के अधिकारों की वकालत करने, उन्हें बढ़ावा देने, उनके शोषण को रोकने, उनका समग्र विकास करने और बच्चों का उत्सव मनाने के लिए एक प्रेरणादायी अवसर के रूप में विश्व बाल दिवस है, यह उस समाज की आत्मपरीक्षा का अवसर है, जो अपने भविष्य को बच्चों की आंखों में देखता है। 20 नवंबर को मनाया जाने वाला यह दिवस हमें याद दिलाता है कि बच्चे केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं। वर्ष 2026 की थीम मेरा दिन, मेरे अधिकार, मेरा भविष्य है। इसी बुनियादी प्रश्न को सामने रखती है कि क्या हमारे बच्चों को वास्तव में अपने अधिकारों के साथ जीने, सपने देखने और अपना भविष्य गढ़ने का अवसर मिल रहा है? भारत में बचपन की तस्वीर विरोधाभासों से भरी है। एक ओर महानगरों के वातानुकूलित कमरों में पलते बच्चे आधुनिक शिक्षा, तकनीक और सुविधाओं से घिरे हैं, तो दूसरी ओर फुटपाथ, झुग्गियों, कारखानों, ढाबों और खेतों में ऐसे बच्चे भी हैं जिनके हाथों में किताब की जगह औजार हैं। किसी बच्चे के लिए बचपन खेल, शिक्षा और परिवार का स्नेह है, तो किसी के लिए भूख, श्रम, हिंसा और असुरक्षा से जूझने का नाम। यह असमानता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना की भी परीक्षा है।

सबसे गंभीर चुनौती बाल हिंसा और मानसिक दबाव की है। हिंसा का



अर्थ केवल बच्चे को पीटना नहीं है। लगातार डांटना, अपमानित करना, डराना, उसकी तुलना दूसरे बच्चों से करना, उसकी इच्छा और प्रतिभा को नकारना तथा हर समय परिणाम का दबाव बनाना भी हिंसा के ही रूप हैं। आज अनेक अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस या किसी प्रतिष्ठित पेशे में जाए। महत्वाकांक्षा गलत नहीं, लेकिन जब माता-पिता की अधूरी इच्छाओं का बोझ बच्चे के कंधों पर रख दिया जाता है, तब शिक्षा विकास का माध्यम न रहकर तनाव का कारण बन जाती है। स्कूल भी इससे अछूते नहीं हैं। अनुशासन के नाम पर अपमान, डर और कठोरता बच्चे के व्यक्तित्व को भीतर से तोड़ सकती है। जिस विद्यालय में बच्चे को प्रश्न पूछने, गलती करने और फिर सीखने का अवसर मिलना चाहिए, वहां भय का वातावरण उसकी रचनात्मकता को कुंठित कर देता है। हमें यह समझना होगा कि डर से आज्ञाकारी बच्चा तो बनाया जा सकता है, लेकिन आत्मविश्वासी नागरिक नहीं।

भारत में बाल मजदूरी, बाल तस्करी, यौन शोषण और भिक्षावृत्ति जैसी समस्याएं आज भी हमारी सामूहिक चेतना एवं राजनीतिक नेतृत्व पर प्रश्नचिह्न हैं। आर्थिक मजबूरी के कारण अनेक बच्चे शिक्षा से दूर होकर श्रम की दुनिया में पहुंच जाते हैं। कुछ खतरनाक उद्योगों और असुरक्षित कार्यस्थलों पर काम करने के लिए विवश होते हैं। कई बच्चे तस्करी के जाल में फंसकर अपने परिवार और बचपन दोनों से दूर हो जाते हैं। सबसे पीड़ादायक स्थिति उन बच्चों की है जिन्हें अपराध, भीख या यौन शोषण के अंधेरे में धकेल दिया जाता है। इन परिस्थितियों में उनसे केवल उनका वर्तमान नहीं छीना जाता, बल्कि भविष्य की संभावनाएं भी छीन ली जाती हैं। गरीबी बचपन की सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन गरीबी से भी बड़ी समस्या है अवसरों की असमानता। यदि किसी गरीब परिवार का बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण से वंचित रहता है तो वह अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कैसे करेगा? विकसित भारत का सपना तभी वास्तविक होगा जब विकास की रोशनी गांव, झुग्गी, श्रमिक परिवार और वंचित समुदाय के बच्चे तक पहुंचेगी। किसी राष्ट्र की प्रगति का सही पैमाना उसके सबसे कमजोर बच्चे की स्थिति है।

इसलिए बाल अधिकारों को केवल कानून की पुस्तकों तक सीमित रखने के बजाय घर, स्कूल और समाज की संस्कृति का हिस्सा बनाना होगा। बच्चे को यह विश्वास होना चाहिए कि वह अपनी समस्या बिना भय के माता-पिता, शिक्षक अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति से कह सकता है। परिवार में संवाद की परंपरा विकसित करनी होगी। माता-पिता को बच्चों के साथ केवल उनकी पढ़ाई और परीक्षा की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके डर, मित्रता, सपनों, असफलताओं और भावनाओं को भी सुनना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में भी बड़ा परिवर्तन आवश्यक है। शिक्षा का लक्ष्य केवल अंक और रोजगार नहीं, बल्कि संवेदनशील, आत्मनिर्भर, नैतिक और मानसिक रूप से स्वस्थ मनुष्य बनाना होना चाहिए। बच्चों को अधिकारों के साथ कर्तव्यों, संविधान, लैंगिक सम्मान, डिजिटल सुरक्षा, आत्मरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक किया जाना चाहिए। सरकार को बाल संरक्षण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ बाल श्रम, तस्करी और यौन अपराधों के विरुद्ध तंत्र को और मजबूत करना होगा। गरीब बच्चों की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य को आर्थिक सहायता से जोड़ना भी जरूरी है। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि बच्चों की सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। पड़ोस में किसी बच्चे से दुर्व्यवहार हो रहा हो, किसी दुकान या कारखाने में बाल मजदूर दिखाई दे, कोई बच्चा लगातार भय में जी रहा हो या उसके साथ शोषण की आशंका हो, तो ह्रहमें क्या लेना-देना हैह्व कहकर आगे बढ़ जाना सामाजिक अपराध के प्रति मौन स्वीकृति है। बच्चे की रक्षा के लिए समाज को संवेदनशील प्रहरी बनना होगा।

विश्व बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के सामने उभरती नई चुनौतियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) भी एक गंभीर विषय बनकर सामने आई है। एआई शिक्षा, रचनात्मकता और ज्ञान-विस्तार का प्रभावी साधन हो सकता है, लेकिन उसका अनियंत्रित और अत्यधिक उपयोग बच्चों की सोचने-समझने की मौलिक क्षमता, कल्पनाशक्ति, एकाग्रता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। चैटबॉट पर अत्यधिक निर्भरता बच्चों को स्वयं प्रश्न पूछने, उत्तर खोजने और गलतियों से सीखने की प्रक्रिया से दूर कर सकती है। साथ ही, एआई से बने भ्रामक या अनुपयुक्त कंटेंट, डीपफेक, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन शोषण, निजता के खतरे और बच्चों के मानसिक संसार पर बढ़ते डिजिटल दबाव जैसी चुनौतियां भी चिंता का विषय हैं। इसलिए आज आवश्यकता केवल बच्चों को एआई से परिचित कराने की नहीं, बल्कि उन्हें एआई के सुरक्षित, संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग की शिक्षा देने की है, ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता बच्चों की बुद्धि का विकल्प नहीं, बल्कि उनकी प्रतिभा और रचनात्मकता को विकसित करने का सहायक माध्यम बने।

विश्व बाल दिवस का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होगा जब भारत में ऐसा वातावरण बने जहां हर बच्चा सुरक्षित हो, सुना जाए, सम्मान पाए, पढ़ सके, खेल सके, अपनी प्रतिभा विकसित कर सके और बिना भय के सपने देख सके। हमें बच्चों को अपने सपनों के अनुसार जीने का अवसर देना होगा, अपने सपनों के अनुसार ढालने का नहीं। बचपन किसी राष्ट्र की प्रतीक्षा करती हुई सुबह है। यदि उस सुबह पर हिंसा, शोषण, भूख और भय के बादल छा गए तो विकसित भारत का सूर्योदय अधूरा रहेगा। इसलिए आज जरूरत केवल बाल दिवस मनाने की नहीं, बल्कि बचपन को बचाने की है। जिस दिन भारत के हर बच्चे की आंखों में भय की जगह विश्वास, हाथों में श्रम की जगह किताब और होंठों पर शिकायत की जगह मुस्कान होगी, उसी दिन हम कह सकेंगे कि हमने विश्व बाल दिवस की भावना को वास्तव में आत्मसात किया है।

चमकती 'वंदे भारत' की आड़ में सिसकता आम यात्री और सत्ता की जवाबदेही



अशोक भाटिया

भारतीय रेल केवल लोहे की पटरियों पर दौड़ने वाला एक यातायात तंत्र भर नहीं है, बल्कि यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले इस विशाल देश की धड़कन, एकता और सामाजिक ताने-बाने की सबसे मजबूत डोर है। उत्तर भारत के किसी छोटे से कस्बे से रोजगार की तलाश में दक्षिण भारत के किसी औद्योगिक शहर की ओर जाने वाला श्रमिक हो, या फिर अपने परिवार के साथ तीर्थयात्रा और किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होने निकला मध्यमवर्गीय नागरिक– भारतीय रेल सदियों से हर वर्ग की आकांक्षाओं को ढोती रही है। किंतु आज भारतीय रेलवे एक ऐसे विरोधाभासी मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ 'हाई-स्पीड' और 'विश्वस्तरीय' आधुनिकता की चमक-दमक है, तो दूसरी तरफ आम यात्री के लिए बुनियादी मानवीय गरिमा और सुरक्षित सफर का गहरा संकट। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने जिस तरह से सेमी-हाई स्पीड 'वंदे भारत' ट्रेनों के विस्तार, बुलेट ट्रेन परियोजनाओं और स्टेशनों के कायाकल्प को अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में प्रचारित किया है, उसने रेल के असल स्वरूप और उसकी प्राथमिकता पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर चमचमाती वातानुकूलित बोगियों को हरी झंडी दिखाने के भव्य सरकारी आयोजन होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं स्टेशनों के दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी साधारण ट्रेनों के जनरल और स्लीपर डिब्बों में भेड़-बकरियों की तरह ठुंसे यात्रियों की तस्वीरें सत्ता की संवेदनहीनता और नीतिगत प्राथमिकताओं की पोल खोलती हैं।

आज देश के किसी भी बड़े रेलवे जंक्शन–चाहे वह उत्तर में नई दिल्ली, पटना, लखनऊ और प्रयागराज हो या दक्षिण में चेन्नई, बेंगलुरु, सिकंदराबाद और कोच्चि–पर जाकर देखा जाए तो दो अलग-अलग भारत एक साथ यात्रा करते नजर आते हैं। एक भारत वह है जो ऊंचे किराए चुकाकर एयरपोर्ट जैसे दिखने वाले स्टेशनों के लाउंज में बैठता है और स्वचालित दरवाजों वाली आधुनिक ट्रेनों में आरामदायक सफर करता है। दूसरा भारत वह है जो अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से टिकट खरीदने के बावजूद ट्रेन के शौचालयों के पास बैठकर या दरवाजों पर लटककर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने को अभिशप्त है। त्योहारों और छुट्टियों के मौसम में तो यह स्थिति किसी मानवीय त्रासदी से कम नहीं होती, लेकिन अब सामान्य दिनों में भी साधारण ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती। विडंबना यह है कि जब सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों से इस अमानवीय भीड़ के बारे में सवाल पूछा जाता है, तो जिम्मेदारी लेने के बजाय इसे यात्रियों की अनुशासनहीनता या बढ़ती आबादी का स्वाभाविक परिणाम बताकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। यह तर्क इस कड़वे सच को छिपाने की राजनीतिक कोशिश है कि पिछले एक दशक में प्रीमियम और वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बों की संख्या तो तेजी से बढ़ाई गई, लेकिन आम आदमी की सवारी कहे जाने वाले अनारक्षित यानी जनरल और नॉन-एसी स्लीपर डिब्बों की संख्या में सुनियोजित तरीके से कटौती की गई।

राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान ने भारतीय रेल को जनसेवा के माध्यम के बजाय अपने चुनावी प्रचार और छवि निर्माण के सबसे बड़े उपकरण में बदल दिया है। जिस राज्य में विधानसभा या लोकसभा के चुनाव नजदीक आते हैं, वहां नई ट्रेनों के लोकार्पण और स्टेशनों के शिलान्यास की झड़ी लग जाती है।

हिन्दी दैनिक
उत्तरशक्ति
मार्गदर्शन

इन आयोजनों को जिस भव्यता के साथ टेलीविजन और सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जाता है, उससे ऐसा आभास होता है मानो देश की रेल व्यवस्था किसी स्वर्णिम युग में प्रवेश कर चुकी है। लेकिन प्रचार के इस चकाचौंध भरे पर्दे के पीछे की जमीनी हकीकत बेहद भयावह है। जब किसी रेल दुर्घटना में दर्जनों निर्दोष नागरिकों की जान जाती है या सिग्नल प्रणाली की विफलता से पटरियों पर खून बहता है, तब न तो कोई नैतिक जिम्मेदारी लेता है और न ही शीर्ष स्तर पर कोई जवाबदेही तय होती है। पुराने दौर में रेल हादसों के बाद मंत्रियों द्वारा इस्तीफा देने की जो लोकतांत्रिक परंपरा थी, उसे आज के आक्रामक पीआर (जनसंपर्क) तंत्र ने पूरी तरह दफन कर दिया है। संकट के समय सुधार करने के बजाय सरकारी मशीनरी का पूरा जोर इस बात पर रहता है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बदहाली के वीडियो को कैसे दबाया जाए और कहानी को कैसे मोड़ा जाए।

इसके साथ ही रेल बजट और परियोजनाओं के आवंटन में क्षेत्रीय असंतुलन और राजनीतिक पक्षपात के आरोप भी लगातार गहराते जा रहे हैं। उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में जहां प्रवासी मजदूरों और निम्न-मध्यम वर्ग के यात्रियों को तीन-तीन दिन तक बिना बुनियादी सुविधाओं के किसी तरह अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ता है, वहीं दक्षिण के कई राज्यों का यह आरोप भी राजनीतिक तूल पकड़ रहा है कि केंद्र सरकार की अधिकांश महत्वाकांक्षी रेल परियोजनाएं और बजटीय आवंटन उन्हीं राज्यों पर केंद्रित हैं जहां सत्तारूढ़ दल को सीधा चुनावी लाभ दिखता है। संघीय ढांचे में बुनियादी ढांचे का विकास राजनीतिक नफा-नुकसान के तराजू पर नहीं तौला जा सकता। जब नीति निर्माण का सारा ध्यान 'प्रीमियम' मतदाताओं और चुनावी समीकरणों पर केंद्रित हो जाता है, तो देश का आम नागरिक खुद को अपने ही देश की सार्वजनिक व्यवस्था में दोयम दर्जे का महसूस करने लगता है। इस पूरे परिदृश्य का एक और अत्यंत चिंताजनक पहलू रेल सुरक्षा और कर्मचारियों के प्रति सरकार का उदासीन रवैया है। आधुनिकता के तमाम दावों के बावजूद आए दिन होने वाली रेल दुर्घटनाएं, पटरियों के रखरखाव में लापरवाही और 'कवच' जैसी सुरक्षा प्रणालियों के धीमे विस्तार ने यह साबित कर दिया है कि बुनियादी ढांचे की नींव को मजबूत किए बिना केवल ऊपरी सजावट पर जोर दिया जा रहा है। रेलवे के भीतर लाखों की संख्या में सुरक्षा और तकनीकी से जुड़े पद वर्षों से खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार नई भर्तियां करने के बजाय ठेका प्रथा और निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। दूसरी तरफ, वीआईपी और प्रीमियम ट्रेनों को समय पर चलाने की होड़ में साधारण पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को घंटों तक आउटर सिग्नल पर खड़ा रखा जाता है। एक दिहाड़ी मजदूर या छोटे व्यापारी के लिए समय की कीमत किसी कॉरपोरेट अधिकारी से कम नहीं होती, लेकिन सत्ता की इस नई कार्यसंस्कृति ने यह मान लिया है कि कम किराया देने वाले गरीब यात्री के समय, उसकी सुविधा और उसके धैर्य की कोई कीमत नहीं है। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को मिलने वाली किराया रियायतों को समाप्त करने का फैसला भी इसी संवेदनहीन और मुनाफाखोर सोच का हिस्सा है, जिससे लाखों बुजुर्गों के लिए अपनों से मिलना या तीर्थयात्रा करना कठिन हो गया है। रेलवे के निजीकरण और व्यावसायीकरण की सरकारी नीतियां कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर सीधा प्रहार हैं। किसी भी सार्वजनिक उपक्रम को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना गलत नहीं है, लेकिन जब एक लोकतांत्रिक सरकार जनसेवा के मूल सिद्धांत को पूरी तरह मुनाफाखोरी की भेंट चढ़ा देती है, तो गरीब और मध्यम वर्ग के पास कोई विकल्प नहीं बचता। रेलवे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ इसलिए नहीं बनी कि उसने मुनाफा कमाया, बल्कि इसलिए बनी कि उसने देश के सबसे गरीब नागरिक को भी सस्ती और सुलभ गतिशीलता प्रदान की। आज सत्ता पक्ष जिस तरह से आम आदमी की जेब पर बोझ डालकर और उसकी बुनियादी सुविधाओं में कटौती करके केवल कुछ चुनिंदा हाई-स्पीड ट्रेनों के जरिए 'विकसित भारत' की तस्वीर पेश कर रहा है, वह लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि केंद्र सरकार आत्ममुग्धता और प्रचार की राजनीति से बाहर निकले और भारतीय रेलवे की प्राथमिकताओं को जमीनी हकीकत के अनुरूप दुरुस्त करे। देश को वंदे भारत और बुलेट ट्रेन की रफ्तार जरूर चाहिए, लेकिन यह रफ्तार साधारण ट्रेनों की पटरियां उखाड़कर या जनरल डिब्बों की बलि देकर हासिल नहीं की जा सकती। सरकार को चाहिए कि वह हर लंबी दूरी की ट्रेन में अनारक्षित और स्लीपर डिब्बों की पर्याप्त संख्या तत्काल बहाल करे, नई जनसाधारण ट्रेनों का परिचालन बढ़ाए और रेलवे के रिक्त सुरक्षा पदों को अविलंब भरे। स्टेशनों के बाहरी सौंदर्यीकरण के साथ-साथ साधारण प्लेटफॉर्मों पर स्वच्छ पेयजल, शौचालय और सुरक्षित प्रतीक्षालयों की व्यवस्था करना सत्ता का संवैधानिक दायित्व है। अंततः, किसी भी सरकार की सफलता उसके चमकते हुए विज्ञापनों या तेज रफ्तार ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने की तस्वीरों से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि उस देश का सबसे साधारण नागरिक अपनी यात्रा के दौरान कितना सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता है। जब तक जनरल डिब्बे में सफर करने वाले आम भारतीय के चेहरे पर सुकून और उसकी यात्रा में गरिमा नहीं लौटती, तब तक सत्ता के तमाम दावे महज एक राजनीतिक छलावा ही माने जाएंगे।

न्याय में देरी लोकतंत्र के विश्वास पर सबसे बड़ी चोट



- डॉ. सत्यवान सौरभ

न्याय केवल न्यायालयों में होने वाली कानूनी प्रक्रिया का नाम नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता, नागरिकों के अधिकारों और संविधान की आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। किसी भी सभ्य समाज में न्याय का वास्तविक महत्व तभी है, जब वह समय पर और प्रत्येक नागरिक की पहुँच में उपलब्ध हो। यदि किसी व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वर्षों तक न्यायालयों के चक्कर लगाने पड़ें, आर्थिक संसाधन समाप्त हो जाएँ और न्याय मिलने से पहले ही उसका जीवन संघर्षों में बीत जाए, तो न्याय का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने लंबित मुकदमों का बढ़ता बोझ और सुनवाई में होने वाली देरी आज गंभीर चुनौती बन चुके हैं। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालयों में शीघ्र सुनवाई न मिलने के कारण वादियों के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचने की चिंता इसी समस्या की गंभीरता को उजागर करती है। यह स्थिति बताती है कि न्यायिक व्यवस्था में केवल मुकदमों का निपटारा बढ़ाना पर्याप्त नहीं, बल्कि न्याय तक पहुँचने की प्रक्रिया को भी सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना आवश्यक है।

भारत में न्यायिक देरी का सबसे प्रमुख कारण न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों का रिक्त रहना है। न्यायालयों में उपलब्ध न्यायाधीशों की संख्या मुकदमों के अनुपात में पर्याप्त नहीं है। परिणामस्वरूप मौजूदा न्यायाधीशों पर अत्यधिक कार्यभार पड़ता है। जब सीमित संख्या में न्यायाधीशों को बड़ी संख्या में मामलों की सुनवाई करनी पड़ती है, तो प्रत्येक मामले को पर्याप्त समय देना कठिन हो जाता है। नियुक्तियों में विलंब, चयन प्रक्रिया की जटिलताएँ और विभिन्न स्तरों पर होने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाएँ इस समस्या को और गंभीर बनाती हैं। न्यायिक पदों को लंबे समय तक रिक्त रखना अंततः आम नागरिक के न्याय पाने के संवैधानिक अधिकार को प्रभावित करता है।

दूसरा बड़ा कारण न्यायालयों में लंबित मुकदमों की विशाल संख्या है। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों तक मुकदमों का लगातार बढ़ता दबाव न्यायिक व्यवस्था की कार्यक्षमता को प्रभावित कर रहा है। नए मुकदमों के आने की गति और पुराने मामलों के निस्तारण के बीच संतुलन स्थापित नहीं हो पा रहा है। कई मामलों में वादी और प्रतिवादी दोनों वर्षों तक निर्णय की प्रतीक्षा करते रहते हैं। दीवानी विवादों, संपत्ति संबंधी मामलों, पारिवारिक विवादों और आपराधिक मुकदमों में देरी का प्रभाव विशेष रूप से गंभीर होता है। आपराधिक मामलों में विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है, जबकि दीवानी मामलों में संपत्ति, व्यवसाय और पारिवारिक संबंध अनिश्चितता में फँसे रहते हैं।

बार-बार होने वाले स्थगन भी न्यायिक देरी का एक प्रमुख कारण हैं। कई बार अधिवक्ताओं की अनुपलब्धता, पक्षकारों की तैयारी पूरी न होना, दस्तावेजों की कमी अथवा अन्य प्रक्रियागत कारणों से सुनवाई आगे बढ़ा दी जाती है। कुछ मामलों में अनावश्यक स्थगन मुकदमों को लंबा खींचने का माध्यम बन जाते हैं। न्यायालयों में तारीख पर तारीख मिलने की प्रवृत्ति न केवल न्यायिक समय की बबार्दी करती है, बल्कि वादियों पर आर्थिक और मानसिक दबाव भी बढ़ाती है। न्याय प्राप्त करने के लिए बार-बार यात्रा करना, अधिवक्ताओं की फीस देना और कामकाज छोड़ना आम नागरिक के लिए अतिरिक्त कठिनाई पैदा करता है।

न्यायिक आधारभूत संरचना की कमी भी इस समस्या को बढ़ाती है। अनेक न्यायालयों में पर्याप्त न्यायालय कक्ष, तकनीकी सुविधाएँ, प्रशिक्षित कर्मचारी और आधुनिक अभिलेख प्रबंधन प्रणाली उपलब्ध नहीं हैं। न्यायिक प्रक्रिया का बड़ा हिस्सा अभी भी दस्तावेजों, भौतिक फाइलों और प्रशासनिक औपचारिकताओं पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त सरकारी मुकदमेबाजी भी न्यायालयों पर अनावश्यक बोझ बढ़ाती है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा छोटे-छोटे मामलों में अपील करना, निर्णयों को चुनौती देना और विवादों का समय रहते समाधान न करना मुकदमों की संख्या बढ़ाता है। सरकार स्वयं देश की सबसे बड़ी वादियों में शामिल है। इसलिए सरकारी विभागों की जवाबदेही और मुकदमेबाजी नीति में सुधार के बिना लंबित मामलों की समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। इस चुनौती से निपटने के लिए सबसे पहले न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाना होगा। उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाना चाहिए। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और तकनीकी विशेषज्ञों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नियुक्तियों की पारदर्शिता बनाए रखते हुए चयन प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब समाप्त करना समय की माँग है। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय प्रभावी केस प्रबंधन है। प्रत्येक मुकदमे की प्रकृति और आवश्यकता के अनुसार सुनवाई की समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। अनावश्यक स्थगनों पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए और विशेष परिस्थितियों को छोड़कर बार-बार तारीख देने से बचना चाहिए। न्यायालयों को मामलों की प्राथमिकता तय करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। वृद्धों, महिलाओं, बच्चों, गंभीर बीमारियों से जुड़े मामलों और लंबे समय से लंबित आपराधिक मामलों को उचित प्राथमिकता दी जानी चाहिए। त्वरित न्याय का अर्थ जल्दबाजी में निर्णय देना नहीं, बल्कि अनावश्यक प्रक्रियागत देरी समाप्त करते हुए निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना है। डिजिटल तकनीक न्यायिक सुधारों का एक प्रभावी माध्यम बन सकती है। ई-फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन केस ट्रैकिंग से न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकता है। भारत में ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से न्यायालयों के डिजिटलीकरण, मामलों की ऑनलाइन जानकारी और तकनीकी सुविधाओं के विस्तार को बढ़ावा मिला है। हालांकि डिजिटल न्याय व्यवस्था का लाभ तभी व्यापक होगा, जब ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे शहरों और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को भी इंटरनेट, डिजिटल साक्षरता और आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए। तकनीक न्याय तक पहुँच का साधन बने, नई बाधा नहीं। इसके साथ ही वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणालियों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। मध्यस्थता, सुलह और लोक अदालतें ऐसे मंच हैं, जहाँ अनेक विवाद पारंपरिक न्यायिक प्रक्रिया की तुलना में कम समय और कम खर्च में सुलझाए जा सकते हैं। पारिवारिक विवाद, छोटे आर्थिक विवाद, बैंक ऋण और आपसी समझौते से हल होने वाले मामलों को इन माध्यमों से निपटाने पर नियमित न्यायालयों का बोझ कम किया जा सकता है। जिला स्तर पर मध्यस्थता केंद्रों को अधिक प्रभावी बनाना और प्रशिक्षित मध्यस्थों की संख्या बढ़ाना भी उपयोगी होगा। सस्ती न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है जितना शीघ्र न्याय। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति केवल इसलिए न्याय से वंचित न रह जाए कि वह अधिवक्ता की फीस या मुकदमे का खर्च वहन नहीं कर सकता। इसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं को मजबूत करना होगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की भूमिका को गाँवों और कस्बों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुँचाना चाहिए। लोगों को उनके कानूनी अधिकारों, उपलब्ध सहायता और शिकायत निवारण के माध्यमों के बारे में जागरूक करना भी जरूरी है। सरकारी मुकदमेबाजी को कम करने के लिए विभागों में प्रभावी विवाद समाधान तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। प्रत्येक छोटे मामले में अपील करने के बजाय अधिकारियों को तथ्यों और कानूनी स्थिति के आधार पर विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अनावश्यक अपीलों और बार-बार चुनौती देने की प्रवृत्ति पर संस्थागत नियंत्रण होना चाहिए। इससे न्यायालयों का बहुमूल्य समय बचेगा और नागरिकों को शीघ्र राहत मिल सकेगी। अंततः न्यायिक सुधार केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने या न्यायालयों के डिजिटलीकरण तक सीमित नहीं हो सकते। इसके लिए न्यायपालिका, सरकार, अधिवक्ता समुदाय और नागरिकों के बीच सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करनी होगी। न्यायालयों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही को मजबूत करना होगा। साथ ही न्यायिक स्वतंत्रता से किसी प्रकार का समझौता किए बिना संस्थागत सुधारों को आगे बढ़ाना होगा। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता और समानता का आश्वासन देता है। इस आश्वासन की सार्थकता तभी है, जब न्याय समय पर मिले और आर्थिक स्थिति किसी व्यक्ति के न्याय पाने के अधिकार में बाधा न बने। वर्षों तक लंबित मुकदमे केवल न्यायिक आँकड़े नहीं होते, बल्कि उनके पीछे लाखों परिवारों की उम्मीदें, संघर्ष और जीवन की अनिश्चितताएँ जुड़ी होती हैं। इसलिए अब आवश्यकता ऐसी न्याय व्यवस्था विकसित करने की है, जहाँ न्याय महज कानूनी अधिकार न होकर प्रत्येक नागरिक का व्यावहारिक अनुभव बने। न्याय में देरी केवल प्रशासनिक कमजोरी नहीं, बल्कि न्याय के उद्देश्य को कमजोर करने वाली स्थिति है। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि न्याय न तो महँगा हो, न जटिल और न ही अनिश्चित प्रतीक्षा का विषय। समय पर और सस्ता न्याय ही संविधान के प्रति नागरिकों के विश्वास को वास्तविक मजबूती प्रदान कर सकता है।

आजम को राहत से बदलेगा पश्चिमी यूपी का सियासी समीकरण



-संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश की सियासत बार-बार करवट बदल रही है। अगले साल के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच इसकी गूंज अब लखनऊ से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गलियारों तक साफ सुनाई देने लगी है। इस बदलते राजनीतिक परिदृश्य में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक हालिया फैसला ऐसा मोड़ लेकर आया है, जिसने न केवल एक कद्दावर नेता को कानूनी राहत दी है, बल्कि सूबे के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी सियासी संजीवनी का काम किया है। प्रवर्तन निदेशालय के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत ने उत्तर प्रदेश के चुनावी गणित को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। सियासी गलियारों में यह चर्चा आम है कि अदालत की यह राहत जितनी आजम खान के व्यक्तिगत जीवन और कानूनी लड़ाई के लिए अहम है, उससे कहीं अधिक यह अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से आजम खान और उनका परिवार तमाम कानूनी उलझनों और मुकदमों के घेरे में था। सलाखों के पीछे रहने के कारण आजम खान की वह बुलंद आवाज, जो कभी रामपुर से उठकर पूरे प्रदेश की सियासत को प्रभावित करती थी, कहीं न कहीं खामोश सी हो गई थी। उनकी गैरमौजूदगी में समाजवादी पार्टी के भीतर एक बड़ा शून्य पैदा हो गया था, खासकर उस मुस्लिम वोट बैंक के बीच, जिसे सपा का सबसे मजबूत आधार माना जाता है। अखिलेश यादव ने 'पीडीए' यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा देकर अपनी जमीन को मजबूत करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जमीनी स्तर पर अल्पसंख्यक समाज के बीच एक ऐसे आक्रामक और अनुभवी चेहरे की कमी लगातार खल रही थी, जो सीधे तौर पर उनकी बात रख सके। हाईकोर्ट द्वारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आजम खान को अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद अखिलेश यादव की त्वरित प्

प्रदूषण के खिलाफ दिया मिर्जा की आवाज को बीएमसी दबा रही है : निखिल रूपारेल



मुंबई (उत्तरशक्ति)। मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद मुंबई महानगरपालिका द्वारा मिटाए गए फिल्म अभिनेत्री दिया मिर्जा का, प्रदूषण के खिलाफ जारी किए गए वीडियो को पुनः रिस्टोर नहीं कर रही है। साफ है कि मुंबई महानगरपालिका भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। यह सीधे-सीधे उच्च न्यायालय की अवमानना है। मुंबई युवक कांग्रेस और महिला कांग्रेस द्वारा दिया मिर्जा द्वारा वायु प्रदूषण के खिलाफ जारी किए गए वीडियो के समर्थन में, खार पश्चिम में आयोजित पत्रकार परिषद में बोलते हुए उत्तर मध्य मुंबई जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष निखिल रूपारेल ने उपरोक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि यदि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद बीएमसी दिया मिर्जा के वीडियो को फिर से जारी नहीं करती है तो युवक कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा, क्यों कि यह बच्चों के भविष्य जुड़ा विषय है। मुंबई महिला कांग्रेस की महासचिव प्रीति चोकसी ने कहा कि एक महिला ने साफ हवा के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए अपनी आवाज उठाई। बीएमसी ने उनकी सराहना करने के बजाय उनकी आवाज को ही दबा दिया। यह हर महिला का अपमान है। इसके पहले निखिल रूपारेल ने बीएमसी आयुक्त श्रीमती अश्विनी भिड़े को भी पत्र लिखकर हाईकोर्ट के आदेश को तुरंत लागू करने की मांग की थी। पत्र में उन्होंने कहा है कि महापौर एक औपचारिक प्रमुख होता है उसके पास बीएमसी के आधिकारिक हैंडल्स से कंटेंट डिलीट करने का आदेश देने की कोई कार्यकारी शक्ति नहीं है। अगर किसी राजनीतिक नेतृत्व को खुश करने के लिए डिलीट किया गया है तो यह प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप का स्पष्ट मामला है। इस अवसर पर निखिल रूपारेल और प्रीति चोकसी के अलावा मुस्तकीम शेख, विकास जैसवार, गंगा प्रसाद शर्मा, साद शेख, किशन निषाद, अरविंद साहनी, फुजैल शेख समेत अनेक लोग उपस्थित रहे।

स्व. इंदिरा गांधी जयंती पर भिवंडी मनपा में ली गयी राष्ट्रीय एकता की शपथ



भिवंडी(उत्तरशक्ति)। भिवंडी मनपा मुख्यालय में गुरुवार, 19 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई गई।महाराष्ट्र शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के 29 दिसंबर 2025 के परिपत्र तथा मनपा आयुक्त अनमोल सागर के निदेर्शानुसार आयोजित कार्यक्रम में उपमहापौर तारिक अब्दुल बारी मोमिन ने इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्पहार अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यालय उपायुक्त विक्रम दराडे विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके पश्चात उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ ली। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग प्रमुख मिलिंद पलसुले, विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता ज्ञानेश्वर वाघमारे, मार्केट विभाग प्रमुख स्नेहल पुण्यार्थी, अग्निशमन अधिकारी नितीन चव्हाण, महापौर के विशेष कार्य अधिकारी अजित महाडिक, बारनिशी विभाग प्रमुख सुरेखा पावडे सहित मनपा के विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

मौसमी बदलाव के दौरान इम्यूनिटी को मजबूत रखना क्यों है महत्वपूर्ण: डॉ. यश चौधरी

मुंबई/पटना। मौसम बदलने के साथ कई स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ जाती हैं। तापमान, नमी और वातावरण में बदलाव के कारण शरीर को खुद को ढालने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इससे सर्दी, खांसी, गले में खराश और थकान जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इस समय अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, मौसम में बदलाव के दौरान संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बदलता तापमान, प्रदूषण, एलर्जी और मौसमी वायरस इसका प्रमुख कारण हैं। बच्चे, बुजुर्ग और कामकाजी लोग इस दौरान अधिक प्रभावित हो सकते हैं। सदियों से च्यवनप्राश आयुर्वेद का एक भरोसेमंद हिस्सा रहा है। आंवला और कई लाभकारी जड़ी-बूटियों से बना च्यवनप्राश शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। बदलते मौसम में इसका नियमित सेवन शरीर को आवश्यक पोषण और इम्यूनिटी सपोर्ट प्रदान कर सकता है। आज, जब लोग बीमार होने के बाद इलाज कराने के बजाय पहले से ही अपनी सेहत का ध्यान रखने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, तब च्यवनप्राश स्वस्थ जीवनशैली का एक सरल और सुविधाजनक हिस्सा बन गया है।

देश भर में हवा की गिरती गुणवत्ता के बीच केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने जारी की पब्लिक हेल्थ अडवाइजरी

मुंबई/पटना। केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने एक पब्लिक हेल्थ अडवाइजरी जारी की है, जिसमें नागरिकों से इस सर्दी में वायु प्रदूषण से बचने के लिए एहतियाती उपाय करने की अपील की गई है। दीवाली के एक हफ्ते से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी पटना की हवा अभी भी खराब यानि पुअर कैटेगरी में बनी हुई है, जब एक्यूआई 280 तक पहुँच गया था। छठ के बाद स्थिति और भी बिगड़ गई है; शहर के एक मॉनिटरिंग स्टेशन पर हवा की गुणवत्ता बहुत खराब यानी 300 के स्तर से ऊपर दर्ज की गई है, क्योंकि सुबह और शाम के समय छाने वाला कोहरा प्रदूषक तत्वों को जमीन के करीब ही रोक लेता है। इस बीच बीमा कंपनी के क्लेम डेटा के मुताबिक सितंबर और अक्टूबर 2025 में सांस की बीमारियों के लिए हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम में 11-11 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जो इस साल के किसी भी दूसरे महीने की तुलना में सबसे अधिक है। वित्तीय वर्ष 25-26 में सांस की बीमारियों के लिए अस्पताल में भर्ती होने वाले 58 फीसदी मरीज 0-12 वर्ष के बच्चे और 60 से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक रहे।

सूर्य जलापूर्ति परियोजना के श्रेय को लेकर मीरा-भायंदर में सियासी घमासान

◆मंत्री प्रताप सरनाईक का विधायक नरेंद्र मेहता पर तीखा हमला, बोले– आप अजगर की तरह पूरे शहर को निगलने बैठे हैं



मीरा-भायंदर (उत्तरशक्ति)। मीरा-भायंदर शहर की महत्वाकांक्षी सूर्य जलापूर्ति परियोजना को लेकर राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ तेज हो गई है। परियोजना के वास्तविक इतिहास और इसके लिए किए गए प्रयासों को लेकर महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री एवं धाराशिव जिले के पालक मंत्री प्रताप सरनाईक ने भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता पर तीखा हमला बोला है। सरनाईक ने विधानसभा की पुरानी कार्यवाही और सरकारी दस्तावेजों का हवाला देते हुए मेहता के दावों पर सवाल उठाए। मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि सूर्य जलापूर्ति परियोजना के लिए उनका संघर्ष वर्ष 2009 से 2014 के बीच लगातार जारी रहा। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2012 और 2013 में उन्होंने विधानसभा में इस परियोजना को लेकर आवाज उठाई थी। वर्ष 2012 में सड़क पर उतरकर आंदोलन भी किया था। उन्होंने कहा कि उस समय परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए, जबकि आज कुछ लोग इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। सरनाईक ने वर्ष 2022 का जिक्र करते हुए कहा कि जब विधायक नरेंद्र मेहता घर बैठे थे, तब उन्होंने स्वयं परियोजना के लिए धनराशि स्वीकृत कराने और काम में तेजी लाने के लिए सरकारी स्तर पर कई महत्वपूर्ण बैठकें की थीं। उन्होंने कहा कि उनके पास अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज और विधानसभा की कार्यवाही के प्रमाण मौजूद हैं। आप अजगर की तरह पूरे शहर को निगलने बैठे हैं।

मंत्री सरनाईक ने अपने बयान में विधायक नरेंद्र मेहता पर निशाना साधते हुए कहा, जो लोग आज सूर्य जलापूर्ति परियोजना का श्रेय लेने के लिए आगे आ रहे हैं, उन्हें पहले इस परियोजना का इतिहास समझना चाहिए। वर्ष 2009 से 2014 के बीच हमने लगातार संघर्ष किया। 2012 और 2013 में विधानसभा में आवाज उठाई और मटका फोड़ो आंदोलन के माध्यम से जनता के पानी के सवाल को प्रमुखता से उठाया। इसके सभी प्रमाण आज भी मेरे पास मौजूद हैं। उन्होंने आगे कहा कि चेना गांव के पास जलकुंड और पानी की टंकी के निर्माण कार्य में जानबूझकर बाधाएं उत्पन्न की गईं। सरनाईक ने आरोप लगाया कि कुछ लोग परियोजना के काम में सहयोग करने के बजाय राजनीतिक विवाद खड़ा कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, ह्लआप अजगर की तरह पूरे शहर को निगलने बैठे हैं। नागरिकों को गुमराह करना बंद कीजिए और परियोजना का वास्तविक इतिहास समझिए। तीन महीने में 218 एमएलडी पानी देने का दावा मंत्री प्रताप सरनाईक ने शहरवासियों को आश्वासन देते हुए कहा कि अगले तीन महीनों में मीरा-भायंदर को 218 एमएलडी पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि केवल लोगों के घरों में नल लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन नलों में नियमित पानी पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने कहा, ह्ललोगों को पता है कि शहर में पानी लाने के लिए वास्तव में कौन प्रयास कर रहा है।

हम अगले तीन महीनों में 218 एमएलडी पानी उपलब्ध कराकर अपने काम को साबित करेंगे। लोगों के घरों में नल लगाए गए हैं, अब हमारा लक्ष्य उन नलों में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराना है ह्ल सूर्य जलापूर्ति परियोजना को लेकर मंत्री प्रताप सरनाईक और विधायक नरेंद्र मेहता के बीच सामने आया यह विवाद अब मीरा-भायंदर की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है।

चेम्बूर में सड़क डांबरीकरण का उद्घाटन संपन्न



मुंबई (उत्तरशक्ति)। चेम्बूर एम वार्ड पश्चिम प्रभाग समिति अध्यक्ष नगर सेविका वार्ड क्रमांक 152 आशा सुभाष मराठे के फंड से महर्षि दयानंद सरस्वती मार्ग रोड नंबर 12 का डाम्बरीकरण कार्य का भूमि पूजन शुभ नारियल तोड़कर स्थानिक समाज सेवी श्री मयार्दा पुरुषोत्तम रामलीला समिति अध्यक्ष कुणाल डॉ ओमप्रकाश अग्रवाल ने किया।

इस मौके पर स्थानीय रहिवासी प्रिया अग्रवाल,नीलिमा हिंदुजा, श्रीनिवास कृष्णन,गौरी कामत (पत्रकार) कांति भाई नागड़ा, रामप्रसाद सैनी,संदीप सिंह,समाज सेवक सुभाष मराठे के अलावा बड़ी संख्या में अनेकों गणमान्य लोग उपस्थित थे।

कुणाल अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक लम्बे समय से हम लोग इस रोड का डाम्बरिकरण की मांग करते आ रहे थे।और इस रोड़ का नूतनीकरण भी जरुरी हो गया था ह्लइसके लिए हम अपने विभाग की सभी समस्याओं का समाधान के लिए सदैव जागरूक रहने वाली आशा ताई मराठे का दिल से आभार व्यक्त कर रहे है।

आपला दवाखाना बंद होने के लिए सेना-भाजपा सरकार जिम्मेदार: कांग्रेस गुटनेता कांचन कुलकर्णी

सरकार की आर्थिक लापरवाही का खामियाजा आम नागरिकों और मरीजों को भुगतना पड़ रहा है



कल्याण (उत्तरशक्ति)। आम और जरूरतमंद नागरिकों को मुफ्त एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किए गए कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र के आपला दवाखाना बंद होने से नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से गरीब मजदूर कामगार महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक इससे प्रभावित हो रहे हैं। यह आरोप KDMC कांग्रेस गटनेता कांचन कुलकर्णी ने लगाया है।

जानकारी के अनुसार आपला दवाखाना संचालित करने वाली लाइफकेयर कंपनी का महाराष्ट्र सरकार पर करीब 1,067 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है। बकाया राशि नहीं मिलने के कारण कंपनी द्वारा राज्य में दवाखाने बंद किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। सरकार की आर्थिक लापरवाही और नियोजनहीन कामकाज का असर सीधे आम नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है, ऐसा आरोप कांचन कुलकर्णी ने लगाया।

कुलकर्णी ने सेना-भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के दौरान जनता को बड़े-बड़े आश्वासन और प्रलोभन देने वाली सरकार आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाने में विफल साबित हो रही है। स्वास्थ्य जनता की मूलभूत जरूरत है और सरकार की बकाया राशि के कारण मरीजों को उपचार से वंचित रखना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि बकाया भुगतान का मुद्दा तत्काल सुलझाकर कल्याण-डोंबिवली सहित पूरे महाराष्ट्र में आपला दवाखाना फिर से शुरू किया जाए, ताकि आम नागरिकों को पहले की तरह मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। कांचन कुलकर्णी ने कहा सरकार की आर्थिक लापरवाही की सजा आम जनता क्यों भुगते जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बंद करें और तत्काल आपला दवाखाना शुरू करें। जनता के स्वास्थ्य अधिकारों के लिए कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा।

सांसद क्रीड़ा संग्राम सीजन-2 बॉक्स क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां तेज

महेश गायकवाड और नवीन गवळी ने किया मैदान का निरीक्षण



कल्याण (उत्तरशक्ति)। 20 नवंबर से सांसद श्रीकांत शिंदे क्रीड़ासंग्राम सीजन-2 की शुरूआत होने जा रही है। इस खेल महोत्सव के तहत कल्याण, भिवंडी और ठाणे शहरों के 32 से अधिक खेल मैदानों पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है।

सांसद क्रीड़ासंग्राम सीजन-2 के अंतर्गत चक्की नाका स्थित कै. अनंतशेठ गवळी इनडोर क्रिकेट अभ्यास केंद्र में बॉक्स क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शिवसेना संपर्क प्रमुख एवं नगरसेवक महेश गायकवाड और नगर सेवक नवीन गवळी ने मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान मैदान की व्यवस्थाओं, प्रतियोगिता के आयोजन और खिलाड़ियों के लिए आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया गया। सांसद क्रीड़ासंग्राम के माध्यम से युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने और स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है, 20 नवंबर से शुरू होने वाले इस खेल महोत्सव में विभिन्न खेलों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

जिला परिषद पालघर में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती



पालघर(उत्तरशक्ति)। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर 19 नवंबर 2026 को जिला परिषद पालघर कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्पहार अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया गया।

जिला पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. प्रकाश हसनालकर एवं कार्यकारी अभियंता (निर्माण) संजय कुलकर्णी के हाथों इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्पहार अर्पित किया गया। इस दौरान डॉ. प्रकाश हसनालकर ने इंदिरा गांधी के कार्यों और देश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ ली तथा देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को बनाए रखने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला कृषि विकास अधिकारी सोमनाथ पिंजारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल कल्याण) व्यंकटराव हुंडेकर, विश्वजीत माने सहित जिला परिषद के विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

अंतर्राष्ट्रीय शौचालय दिवस पर पालघर में स्वच्छ शौचालय-गरिमामय भविष्य अभियान का शुभारंभ

◆10 दिसंबर तक चलेगा विशेष अभियान, सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों की स्वच्छता, सुरक्षा व सुविधाओं में होगा सुधार



पालघर(उत्तरशक्ति)। अंतर्राष्ट्रीय शौचालय दिवस के अवसर पर पालघर जिले में 19 नवंबर से 10 दिसंबर 2026 तक स्वच्छ शौचालयझ्झगरिमामय भविष्य विशेष अभियान शुरू किया गया है। केंद्र सरकार के जलशक्ति मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों की स्वच्छता, सुरक्षा, कार्यक्षमता और सुविधाओं को बेहतर बनाना है। इस वर्ष विश्व शौचालय दिवस की थीम सुरक्षित शौचालय, समान भविष्य रखी गई है। यह जानकारी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे ने दी। अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ ग्राम पंचायत केलवे में सार्वजनिक शौचालय के लोकार्पण के साथ किया गया। इसके अलावा विक्रमगढ़ तालुका के डोलारी खुर्द और इंदगांव में भी सार्वजनिक शौचालयों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के पदाधिकारी, जल एवं स्वच्छता मिशन कक्ष के कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

अभियान के तहत 20 नवंबर से 8 दिसंबर तक ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का निरीक्षण किया जायेगा। इस दौरान पानी की उपलब्धता, बिजली व्यवस्था, साफ-सफाई, आवश्यक सामग्री, मल-मूत्र प्रबंधन तथा नियमित रखरखाव एवं मरम्मत की स्थिति का जायजा लिया जायेगा। आवश्यकता के अनुसार शौचालयों की मरम्मत, रंगरोगन और सौंदर्यीकरण भी किया जायेगा। साथ ही व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की स्थिति की जांच कर लाभार्थियों को आवश्यक सुधार के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। अभियान के अंतर्गत स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में स्थित शौचालयों का भी निरीक्षण किया जायेगा। विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वच्छता, साफ-सफाई और साबुन से हाथ धोने के महत्व के प्रति जागरूक किया जायेगा। इसके साथ ही स्कूल स्वच्छता परीक्षण भी किया जायेगा। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शौचालयों के उपयोग में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक सुविधाओं और सुधारों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। अभियान के तहत उत्कृष्ट सार्वजनिक, सामुदायिक, संस्थागत एवं व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के चयन के लिए प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति स्तर पर चयनित उत्कृष्ट शौचालयों को अभियान के समापन समारोह में सम्मानित किया जायेगा।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे एवं जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के परियोजना संचालक संजय भोये ने सभी ग्राम पंचायतों से सार्वजनिक शौचालयों की नियमित सफाई, रखरखाव और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने की अपील की है। साथ ही नागरिकों से स्वच्छता की अच्छी आदतें अपनाने और इस अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाने का आहवान किया है।

21 नवंबर को समान नागरिक संहिता पर होगी जनसुनवाई

◆कोंकण विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में पालघर के लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रख सकेंगे अपनी राय

पालघर(उत्तरशक्ति)। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में नागरिकों, विभिन्न संस्थाओं एवं हितधारक समूहों के सुझाव, आपत्तियां और विचार जानने के उद्देश्य से कोंकण विभाग की ओर से पालघर जिले के लिए विशेष जनसुनवाई आयोजित की गई है। यह जनसुनवाई आगामी 21 नवंबर 2026 को दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक होगी। इसमें जिले के नागरिकों को समान नागरिक संहिता के विभिन्न पहलुओं पर अपनी राय रखने का अवसर मिलेगा। कोंकण विभाग की जनसुनवाई समिति के माध्यम से आयोजित इस प्रक्रिया की अध्यक्षता कोंकण विभागीय आयुक्त करेंगे। जनसुनवाई नवी मुंबई स्थित कोंकण भवन में विभागीय आयुक्त कार्यालय की पहली मंजिल पर स्थित समिति सभागृह में होगी। वहीं पालघर जिले के नागरिकों की सुविधा के लिए जिलाधिकारी कार्यालय, पालघर में भी व्यवस्था की गई है। यहां उपस्थित नागरिकों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जायेगी। इस जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य समान नागरिक संहिता को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों की राय, सुझाव, आपत्तियां एवं विचार जानना है। इसके लिए विषय में रुचि रखने वाले नागरिकों, विभिन्न सामाजिक एवं अन्य संस्थाओं तथा हितधारक समूहों के प्रतिनिधियों से सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की गई है। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जनसुनवाई में शामिल होने वाले नागरिकों को निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पहले उपस्थित होना आवश्यक है। इसके अलावा जो नागरिक केवल ऑनलाइन माध्यम से अपनी राय और सुझाव देना चाहते हैं, उनके लिए महाराष्ट्र शासन की ओर से अलग पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। महाराष्ट्र शासन के आधिकारिक पोर्टल https://ucc.maharashtra.gov.in/ पर समान नागरिक संहिता से संबंधित 37 मुद्दों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। नागरिक इन मुद्दों का अध्ययन कर पोर्टल के माध्यम से अपने विचार एवं सुझाव ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस जनसुनवाई के माध्यम से पालघर जिले के नागरिकों को समान नागरिक संहिता के संबंध में अपनी बात संबंधित समिति तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। अपर जिलाधिकारी सुभाष भागाडे ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाइन माध्यम से इस प्रक्रिया में भाग लेकर अपने सुझाव, विचार एवं आपत्तियां दर्ज कराएं।

उत्तरशक्ति
* संपादकः ओमप्रकाश प्रजापति
* उप संपादकः प्रेम चंद मिश्रा
*प्रबंध संपादकः डा. शेषधर बिन्द
उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।
पत्राचार कार्यालय:
उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)
मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल ऑटाफ हिल वडाला, मुंबई-37
मो.- 9554493941
email ID- uttarshaktinews@gmail.com



स्वामी: शरद फागूराम प्रजापति, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट क्रमांक 4, तल मजला, एन.के. इंडस्ट्रियल स्टेट, आरे रोड, प्रवासी इंडस्ट्रियल एस्टेट, जवल, गेट क्रमांक 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063, महाराष्ट्र से मुदित एवं के-4, रूम नं. 8, ग्राउंड फ्लोर न्यू समता सहकारी को.ऑ. हां. सोसाइटी, एमएमआरडीए कॉलोनी कंजूरमार्ग (वेस्ट), जिला मुंबई- 400078, महाराष्ट्र से प्रकाशित। RNI NO. MAHHIN/2018/76092 * संपादक- ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति, समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के लिए उत्तरदाई तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद मुंबई न्यायालय के अधीन होंगे।
पत्राचार कार्यालय: मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5 ए-337 ट्रैक टर्मिनल, डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल, ऑटाफ हिल, वडाला मुंबई -37, मो.- 9554493941 email ID- uttarshaktinews@gmail.com

हर राज्य में पर्यावरण एवं जल संसाधन विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं: मोहम्मद अरशद खान

पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन और जैव विविधता पर शोध के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र



जौनपुर (उत्तरशक्ति)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं जौनपुर सदर के पूर्व विधायक मोहम्मद अरशद खान ने देश में बढ़ते पर्यावरण संकट, वायु प्रदूषण, घटते वन क्षेत्र, प्रदूषित नदियों और विलुप्त होती वन्यजीव प्रजातियों पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजकर प्रत्येक राज्य में पर्यावरण एवं जल संसाधन विश्वविद्यालय तथा आधुनिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की मांग की है।

मोहम्मद अरशद खान ने कहा कि गंगा, यमुना और गोमती सहित देश की प्रमुख नदियां प्रदूषण की समस्या से जूझ रही हैं। वहीं गौरैया, गिद्ध, तितलियों और अन्य पक्षियों एवं वन्यजीवों की संख्या में कमी जैव विविधता के लिए चिंता का विषय है।

उन्होंने अपने सात सूत्रीय प्रस्ताव में प्रत्येक राज्य में पर्यावरण एवं जल संसाधन विश्वविद्यालय की स्थापना, आधुनिक अनुसंधान केंद्रों का निर्माण, नदियों और तालाबों का संरक्षण, वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा, वायु और जल प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण, स्कूल-कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा तथा इस क्षेत्र में विशेष बजट और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से पर्यावरण विज्ञान, जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में विशेषज्ञ तैयार होंगे। साथ ही युवाओं को शिक्षा, शोध और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। प्रत्येक राज्य की स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान भी विकसित किया जा सकेगा।अंत में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर राष्ट्रीय स्तर पर ठोस नीति बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण देना हम सभी का नैतिक एवं राष्ट्रीय दायित्व है। प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी मानव सभ्यता सुरक्षित रहेगी।

भूमि विवादों के समाधान के लिए मछलीशहर में जुटे अधिकारी, अधिवक्ता और पत्रकार, पत्रकारों का हुआ सम्मान

भूमि विवाद समाधान संवाद 2026 में प्रशासनिक पारदर्शिता, कानूनी जागरूकता और त्वरित न्याय पर हुआ मंथन



अरशद अली

मछलीशहर,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जमीन से जुड़े विवादों के समाधान और आम जनता को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से बुधवार, 18 नवंबर को प्रयागराज रोड स्थित होटल रिया रॉयल में 'भूमि विवाद समाधान संवाद 2026' एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में न्याय, प्रशासन और पत्रकारिता जगत से जुड़ी प्रमुख हस्तियों ने एक मंच पर जुटकर भूमि विवादों के निस्तारण और जनसमस्याओं के समाधान पर विचार-विमर्श किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनोज कुमार मिश्रा, विभागाध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग ने अपने संबोधन में प्रशासनिक पारदर्शिता और कानूनी जागरूकता को आवश्यक बताया। वक्ताओं ने कहा कि भूमि विवादों को शुरूआती स्तर पर ही सुलझाने के लिए प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। इससे आम नागरिकों को अनावश्यक मुकदमेबाजी और परेशानियों से राहत मिल सकती है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जौनपुर पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष शशि मोहन सिंह क्षेम तथा मछलीशहर इकाई के अध्यक्ष अनिल कुमार पांडेय ने निष्पक्ष एवं जिम्मेदार पत्रकारिता की भूमिका पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम के आयोजक एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता पंकज दुबे ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि संवाद का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को भूमि विवादों से संबंधित सही कानूनी जानकारी और प्रशासनिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें न्याय पाने में सहूलियत मिल सके।

इस अवसर पर सामाजिक सरोकारों और जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भूमि विवादों के समाधान के लिए आपसी समन्वय, जागरूकता और प्रभावी कार्यवाही को महत्वपूर्ण बताया गया।

नाहरपुर की दो बस्तियों का रास्ता कच्चा

पटेल और यादव बस्ती के लोगों को आने-जाने में परेशानी, बारिश में कीचड़ और जलभराव से बुजुर्गों और मरीजों को दिक्कत



महराजगंज, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। महराजगंज स्थित नाहरपुर गांव की पटेल और यादव बस्ती तक जाने वाला रास्ता अब तक कच्चा है। सड़क नहीं बनने से दोनों बस्तियों के लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है। बारिश में रास्ते पर कीचड़ और पानी भर जाता है। ग्रामीणों के मुताबिक, तब उन्हें दूसरे रास्ते से घूमकर आना-जाना पड़ता है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बबलू पटेल, राजमणि यादव, अखिलेश यादव, इंद्रमणि यादव, सुरेश विश्वकर्मा, शिवकुमार विश्वकर्मा और अन्य ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारियों से रास्ता बनवाने की मांग की है। उन्होंने रास्ते पर इंटरलॉकिंग कराने की भी मांग की, ताकि लोगों को आने-जाने में आसानी हो।

रोहनिया विधायक ने दिव्यांगजनों को वितरण किया विभिन्न सहायक उपकरण व मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। जनपद के रोहनिया अमरावती पुरुषोत्तम राजकीय बहुउद्देशी दिव्यांग संस्थान खुशीपुर में गुरुवार को जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राम प्रकाश सिंह के मार्गदर्शन में सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि रोहनिया विधायक डॉ सुनील पटेल व जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राम प्रकाश सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलन कर किया। मुख्य अतिथि रोहनिया विधायक डॉ सुनील पटेल ने 179 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कान की मशीन, बैशाखी, एमआर किट, आईडी किट आदि विभिन्न सहायक उपकरण एवं 15 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल निःशुल्क वितरित किए। विधायक डॉ सुनील पटेल ने कहा कि सरकार की योजनाओं से दिव्यांगजन मोटराइज्ड एवं अन्य सहायक उपकरण पाकर आत्मनिर्भर होकर मजबूत होंगे।जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राम प्रकाश सिंह ने सरकार व विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन उपकरणों से उन्हें आने-जाने और दैनिक-कार्यों में सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत जिला दिव्यांग जन अधिकारी राम प्रकाश सिंह तथा प्रभारी रमेश सिंह व संचालन अरविंद सिंह एवं धन्यवाद ज्ञापन सौरभ सिंह ने किया। कार्यक्रम में अजीत पटेल, नरेंद्र पटेल, मानस सिंह, राजकुमार वर्मा, श्याम बली पटेल, विनोद पटेल ,कमलेश कुमार, माधुरी सिंह, प्रदीप यादव, आलोक त्रिपाठी, अनीता यादव, प्रदीप उपाध्याय, विनोद कुमार मौर्य, रिंकू कमलेश समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।

ठंड और नमी से पशुओं में निमोनिया का खतरा, पशु चिकित्साधिकारी ने बताए बचाव के उपाय

महराजगंज, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। बदलते मौसम और बढ़ती ठंड के बीच पशुओं में निमोनिया का खतरा बढ़ गया है। ठंडी हवा, नमी और गंदगी के कारण पशुओं के फेफड़ों में संक्रमण हो सकता है। इसे देखते हुए पशु चिकित्साधिकारी डॉ. सचिन सिंह ने पशुपालकों को सतर्क रहने और पशुओं की विशेष देखभाल करने की सलाह दी है।

डॉ. सचिन सिंह ने बताया कि निमोनिया होने पर पशुओं को तेज बुखार, खांसी, नाक से पानी बहने और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। पशु खाना-पीना कम कर देते हैं और सुस्त रहने लगते हैं। ऐसे लक्षण दिखने पर तत्काल पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने पशुपालकों को सलाह दी कि पशुओं को ठंडी हवा से बचाकर सूखी, साफ और सुरक्षित जगह पर रखें। गीली जमीन पर न बांधें और बिछावन नियमित रूप से बदलते रहें। ठंड के मौसम में संतुलित एवं पौष्टिक आहार के साथ स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि बीमार पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और बिना पशु चिकित्सक की सलाह के कोई दवा या एंटीबायोटिक न दें। समय पर बीमारी की पहचान और उचित उपचार से पशुओं को गंभीर संक्रमण से बचाया जा सकता है।

स्कॉर्पियो से कुचलने की घटना में तीसरी मौत, बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में राजदेव ने तोड़ा दम

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के चक मुफ्तफाबाद में जमीनी विवाद के दौरान स्कॉर्पियो से कुचलने की घटना में घायलों में शामिल 70 वर्षीय राजदेव यादव की बुधवार की रात में मौत हो गई। गंभीर हालत में उन्हें वाराणसी के बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य घायलों का उपचार जारी है।

कोहरे के चलते आपस में टकराई कई गाड़ियां, तीन की मौत व 14 घायल

आजमगढ़ (उत्तरशक्ति)। जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार की सुबह धुंध के कारण पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। लखनऊ की तरफ से आ रही तेज रफ्तार निजी बस सामने चल रहे ट्रेलर में पीछे से जा घुसी। इसके बाद बस के पीछे आ रहीं कई गाड़ियां भी एक-दूसरे से टकराती चली गईं। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के फखरुद्दीनपुर गांव के पास यह हादसा हुआ। सुबह धुंध के कारण दृश्यता कम होने से निजी बस चालक सामने चल रहे ट्रेलर को देख नहीं सका और बस सीधे उसमें जा घुसी। बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद पीछे से आ रहे वाहनों में भी टक्कर होती चली गई। हादसे में दो बस, पांच ट्रक क्षतिग्रस्त हुए। इससे एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही मुबारकपुर थाना प्रभारी प्रदीप मिश्र समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सामान्य कराने का प्रयास किया गया। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ समय तक आवागमन प्रभावित रहा।

पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कार्यालय में सुनीं फरियादियों की समस्याएं, त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह ने गुरुवार को पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई कर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याओं और शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना। उन्होंने



संबंधित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पीड़ितों की समस्याओं को प्राथमिकता से लेते हुए उन्हें न्यायोचित सहायता उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कांग्रेसियों ने संकल्प दिवस के रूप में मनाई इंदिरा गांधी की जयंती

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमला प्रसाद तिवारी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकताओं ने संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए स्थानीय चौक पर स्थापित श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन



किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रामचन्द्र मिश्र ने कहा कि इंदिरा गांधी शक्तिशाली नेता थी उनके कार्यकाल में भारत विश्व के शक्तिशाली देशों में गिना जाता था, वे एकमात्र जनता की विश्वसनीय नेता थी।कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी राकेश मिश्रा ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी अदम्य साहस और शौर्य की प्रतीक थी, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर बंग्लादेश का निर्माण करके इंदिरा गांधी जी ने पूरे विश्व को चौंका दिया था। कांग्रेस नेता राकेश मिश्रा ने आगे कहा कि देश के विकास में श्रीमती इंदिरा गांधी जी का बीस सूत्रीय कार्यक्रम, बैंकों का राष्ट्रीय करण ने भारत को बुलंदियों पर पहुंचाया। इस मौके पर ब्लाक कांग्रेस कमेटी बदलापुर के अध्यक्ष महात्मा प्रसाद शुक्ला, दूधनाथ तिवारी, बाबूराम यादव, अमन शुक्ला, सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

कौशलेंद्र सिंह बने भाजपा किसान मोर्चा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। जनपद के राजातालाब आराजी लाइन विकासखंड क्षेत्र के टडिया जखिखनी निवासी कौशलेंद्र सिंह को भाजपा किसान मोर्चा काशी क्षेत्र का क्षेत्रीय मंत्री बनाया गया है। कौशलेंद्र सिंह कृषि क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित चन्द्रशेखर सिंह के सुपुत्र हैं।कौशलेंद्र सिंह के कुशल नेतृत्व से संगठन को नई मजबूती मिलेगी और किसानों के हितों को नई दिशा मिलेगी। कौशलेंद्र सिंह लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं। उनकी सक्रियता को देखते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। कौशलेंद्र सिंह ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने जो विश्वास जताया है, उस पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करूंगा। किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना तथा कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना मेरी प्राथमिकता होगी। किसान मोर्चा को काशी क्षेत्र में मजबूत किया जाएगा। गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद किया जाएगा क्योंकि किसान ही देश की रीढ़ हैं। पिता के सम्मान से प्रेरणा लेकर उनकी खुशहाली के लिए संघर्ष करूंगा।





कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहें विद्यार्थी: डॉ.रमाकांत क्षितिज

सुल्तानपुर (उत्तरशक्ति)। शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होती, बल्कि जीवन को समझने, स्वयं को पहचानने और चुनौतियों से लड़ने की क्षमता विकसित करना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसी सोच को साकार करते हुए हनुमत इंटर कॉलेज सुल्तानपुर में विद्यार्थियों के मानसिक, शैक्षिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुंबई से आए प्रख्यात दार्शनिक चिंतक, प्रेरक वक्ता एवं लेखक डॉ. रमाकांत तिवारी ह्यक्षितिजह्न ने छात्र-छात्राओं को जीवन में सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और एकाग्रता का महत्व समझाया।कार्यक्रम में डॉ. क्षितिज ने विद्यार्थियों को किशोरावस्था में आने वाले मानसिक, भावनात्मक और शैक्षिक उतार-चढ़ाव के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि जीवन में आने वाली समस्याएं असफलता का संकेत नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर होती हैं। मन को मजबूत बनाकर और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर कठिन परिस्थितियों का भी सामना किया जा सकता है। उन्होंने सात चक्रों की साधना, योग और ध्यान की विभिन्न विधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वयं से जुड़ने का संदेश दिया। उनके मार्गदर्शन में संगीत और ध्यान का अनूठा समन्वय देखने को मिला।



संगीत की मधुर धुनों के बीच विद्यार्थियों को मानसिक शांति, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक अनुभूति कराने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर जीवन की वास्तविक चुनौतियों के लिए भी तैयार करना रहा।

प्रधानाचार्य धर्मेन्द्र कुमार उपाध्याय ने डॉ. रमाकांत क्षितिज के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण और सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने वाले विद्यालय के शिक्षकों, सहयोगियों एवं छात्र-छात्राओं की सराहना की। गौरतलब है कि मुंबई में निवास करने वाले डॉ. रमाकांत तिवारी ह्यक्षितिजह्न जब भी अमेठी आते हैं, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से समाज को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करते हैं। शिक्षा, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना से जुड़े उनके आयोजन क्षेत्र में विशेष चर्चा का विषय बनते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यक्ष नंदकुमार सिंह, प्रबंधक सुरेन्द्र सिंह, प्रधानाचार्य धर्मेन्द्र कुमार उपाध्याय, सुरेश सिंह, जितेन्द्र सिंह, कैलाशनाथ सिंह, कमलाकर तिवारी, हरिश्चंद्र सिंह, पीयूष राय तथा पत्रकार शशिकांत तिवारी, श्रीकांत तिवारी, यश तिवारी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

अमित मिश्रा बने दुद्धी कोतवाली के नए प्रभारी निरीक्षक

विश्वनाथ प्रताप सिंह के मिर्जापुर स्थानांतरण के बाद पुलिस अधीक्षक ने सौंपी जिम्मेदारी, कानून-व्यवस्था संभालेंगे नए कोतवाल



दुद्धी, सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। दुद्धी कोतवाली को नया प्रभारी निरीक्षक मिल गया है। मिजार्पुर जनपद से स्थानांतरित होकर आए अमित कुमार मिश्रा को पुलिस अधीक्षक सोनभद्र ने कोतवाली दुद्धी की कमान सौंपी है। उनके कार्यभार संभालने के साथ ही क्षेत्र की कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग की जिम्मेदारी अब उनके हाथों में होगी।

गौरतलब है कि दुद्धी कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह का चुनावी दृष्टिकोण से मिजार्पुर जनपद में स्थानांतरण कर दिया गया था। उनके स्थानांतरण के बाद दुद्धी कोतवाली में नए प्रभारी निरीक्षक की तैनाती की आवश्यकता थी। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक सोनभद्र ने अमित कुमार मिश्रा को कोतवाली दुद्धी का प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया है।

अमित कुमार मिश्रा के समक्ष अब क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, फरियादियों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास कायम रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। उनकी तैनाती से क्षेत्रवासियों को बेहतर पुलिस व्यवस्था और प्रभावी कानून-व्यवस्था की उम्मीद है।

कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कै किया नमन

विश्व की सबसे शक्तिशाली नेता थी श्रीमती इंदिरा गांधी: डा.प्रमोद कुमार सिंह

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी जौनपुर के अध्यक्ष डा प्रमोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन जयंती समारोह आयोजित कर पार्टी कार्यकताओं ने इंदिरा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष डा प्रमोद कुमार सिंह ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को विश्व की सबसे ताकतवर नेता बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में गणना होती थी। डा. प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी दूरदर्शी नेता थी, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर बंग्लादेश का निर्माण किया, उन्होंने भारत को परमाणु सम्पन्न देश बनाते हुए देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरिफ खान ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी बताते हुए



कहा कि पाकिस्तान के एक लाख शशस्त्र सैनिकों को आत्मसमर्पण कराकर भारतीय सेना और देश को गौरवान्वित कराया, उनके निर्णय राष्ट्र की प्रगति में मील का पत्थर साबित हो रहा है। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी किसान प्रकोष्ठ के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सलामत अली का पार्टी कार्यालय पर कांग्रेसियों ने माला पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत व अभिनंदन किया। इस मौके पर जिला सचिव इरशाद खान, राजीव निषाद,राजकुमार गुप्ता, जब्बार अली सलमानी, मुहम्मद ताहिर, प्रवेश निषाद, राजेश गौतम, इकबाल हुसैन, सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कराने की मांग को समर्थन

प्रदेशव्यापी पदयात्रा पर निकले अधिवक्ता राहुल चौधरी को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सोनभद्र ने दिया समर्थन पत्र

सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सोनभद्र द्वारा अधिवक्ताओं की सुरक्षा एवं सम्मान से जुड़ी अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कराने की मांग को लेकर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में पदयात्रा कर रहे अधिवक्ता राहुल चौधरी को समर्थन प्रदान किया है। एसोसिएशन की ओर से उन्हें समर्थन पत्र दिया तथा इस अभियान के प्रति एकजुटता व्यक्त की गई।

डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह एड ने कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग हैं और समाज में न्याय एवं विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं पर हमले, धमकी एवं उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया जाना समय की आवश्यकता है।

पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन कुमार सिंह एडवोकेट ने कहा ने कहा कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होने से अधिवक्ताओं को अपने विधिक दायित्वों का निर्वहन निर्भीक होकर करने में मदद मिलेगी।

डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सोनभद्र ने अधिवक्ता राहुल चौधरी के अभियान को समर्थन देते हुए अधिवक्ताओं की सुरक्षा, सम्मान एवं अधिकारों की रक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम शीघ्र लागू किए जाने की मांग उठाई। बैठक का संचालन महामंत्री राजेंद्र कुमार यादव एडवोकेट ने किया।

इस अवसर पर प्रेम प्रताप विश्वकर्मा, राजेश कुमार यादव, प्रदीप कुमार मौर्य, मृगराज सिंह, बीपी सिंह, सुरेंद्र चौरसिया, दशरथ यादव, सुरेश सिंह कुशवाहा, संतोष यादव,चतुर्भुज शर्मा, आदर्श देव पांडेय,नवीन पांडेय आदि अधिवक्ता गण उपस्थित रहे।

गजाधरपुर में गद्दोपुर-पूरालाल मार्ग पर हादसे का खतरा, ग्रामीणों ने जल्द पुलिया निर्माण की किया मांग

दिलशाद अहमद सानू

महराजगंज, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। गजाधरपुर गांव से गुजरने वाली शारदा सहायक नहर पर गद्दोपुर-पूरालाल मार्ग की पुलिया टूट गई है। नहर के दोनों तरफ पुलिया क्षतिग्रस्त होने से यहां से गुजरने वाले लोगों को हादसे का खतरा है। इस मार्ग से रोज छोटे-बड़े वाहन और बड़ी संख्या में ग्रामीण आते-जाते हैं। दिन में लोग रास्ते का अंदाजा लगाकर निकल जाते हैं, लेकिन रात में पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों को नहर का किनारा दिखाई नहीं देता। नहर में हमेशा पानी रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया टूटने से यहां हादसे की आशंका बनी रहती है। उनका आरोप है कि संबंधित विभाग ने अब तक पुलिया बनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ग्रामीणों ने विभाग के अधिकारियों से नहर के दोनों तरफ जल्द मजबूत पुलिया बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे लोगों की सुरक्षा होगी और किसी घटना से पहले समस्या का समाधान हो सकेगा।



मड़ियाहूं में 409 जोड़ों का मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हुआ विवाह



मड़ियाहूं, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत रामलीला मैदान मड़ियाहूं में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इसमें जनपद के सात विकास खंडों रामपुर, रामनगर, मड़ियाहूं, जलालपुर, सिरकोनी, बरसठी और मछलीशहर के कुल 409 पात्र जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में विधायक मड़ियाहूं डॉ. आरके पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष मछलीशहर अजय सिंह, मुख्य विकास अधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने नवविवाहित जोड़ों को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। इस आयोजन के लिए कुल 464 जोड़ों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें से 409 पात्र जोड़ों ने सहभागिता कर योजना के तहत विवाह संपन्न कराया।

विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों को लेकर मतदान कार्मिकों के डेटाबेस तैयार करने हेतु प्रशिक्षण बैठक सम्पन्न



जौनपुर (उत्तरशक्ति)। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सकुशल ढंग से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत मतदान कार्मिकों का डेटाबेस तैयार करने के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार जौनपुर में प्रशिक्षण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिए गए निदेशों के क्रम में मतदान कार्मिकों का डेटाबेस निर्धारित समयसीमा के भीतर तैयार किए जाने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान Election Personnel Deployment System (EPDS) के अंतर्गत विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड किए जाने तथा डेटा फीडिंग की प्रक्रिया के संबंध में चर्चा की गई। प्रशिक्षण के दौरान तकनीकी कार्मिकों द्वारा जनपद के समस्त विभागों के संबंधित पटल सहायकों एवं कंप्यूटर ऑपरेटरों को डेटा एंट्री की प्रक्रिया, आवश्यक तकनीकी पहलुओं तथा पोर्टल पर सूचनाएं दर्ज करने के संबंध में विस्तारपूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साथ ही डेटा फीडिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों एवं त्रुटियों से बचने के उपायों की भी जानकारी दी गई। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) परमानन्द झा ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि मतदान कार्मिकों का डेटाबेस तैयार करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। सभी विभाग अपने यहां कार्यरत कार्मिकों का सही एवं पूर्ण विवरण निर्धारित समयसीमा के भीतर पोर्टल पर फीड कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि डेटा फीडिंग में किसी भी प्रकार की त्रुटि या लापरवाही न हो तथा सभी सूचनाओं का सावधानीपूर्वक सत्यापन भी किया जाए, जिससे निर्वाचन के दौरान मतदान कार्मिकों की तैनाती की प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पन्न कराई जा सके। बैठक में जिला विकास अधिकारी मीनाक्षी देवी सहित अधिकारीगण, संबंधित पटल सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

इंदौर में रणजीत हनुमान मंदिर में आंवला नवमी पर अन्नकूट महोत्सव संपन्न



-प्रणित नरेंद्र तिवारी

इंदौर (उत्तरशक्ति)। आंवला नवमी पर बुधवार को शहर के प्रमुख मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव और भंडारों का आयोजन किया गया। रणजीत हनुमान मंदिर में करीब 140 साल पुरानी परंपरा के तहत चलित भंडारा हुआ। यहां करीब 75 हजार श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी तैयार की गई। साथ ही शहर के 101 मंदिरों में भगवान के भोग के लिए प्रसाद भेजा गया। वहीं, वीर अलीजा सरकार मंदिर में भी करीब 50 हजार श्रद्धालुओं के लिए अन्नकूट प्रसादी बनाई गई।मंदिर में शाम 5 बजे महाआरती के बाद अन्नकूट भंडारा शुरू हुआ। भगवान का केसर और स्वर्ण आभूषणों से विशेष शृंगार किया गया। करीब 50 हजार लोगों के लिए पूड़ी, नुक्ती, रामभाजी, पेठा और सेव तैयार किए गए। प्रसादी बनाने में 7500 किलो आटा, 1500 किलो बेसन, 2000 किलो शकर, 125 डिब्बे घी और करीब 200 डिब्बे तेल का उपयोग हुआ। इसके लिए लकड़ी और गैस की 24 भट्टियां लगाई गई थीं।रणजीत हनुमान मंदिर में सुबह 10 बजे अभिषेक के बाद भगवान का विशेष शृंगार किया गया। शाम को 56 भोग अर्पित किए गए। शाम 6.30 बजे महाआरती के बाद चलित भंडारा शुरू हुआ। मुख्य पुजारी पं. दीपेश व्यास के अनुसार, करीब 75 हजार श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी तैयार की गई। भंडारे की व्यवस्था के लिए करीब 700 सेवादार तैनात किए गए थे। सुरक्षा गार्ड, पुलिस और ट्रैफिक टीम ने भी व्यवस्था संभाली। मंदिर परिसर में 82 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई। भंडारे के चलते मंदिर के सामने की एक लेन बंद रखी गई थी। वाहनों के लिए अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आठ कतारें बनाई गई थीं। इनमें चार पुरुषों और चार महिलाओं के लिए थीं। काउंटर से पूड़ी, रामभाजी, नुक्ती और भजिए के पैकेट वितरित किए गए। मंदिर से शहर के 101 मंदिरों में भी प्रसाद भेजा गया।

मैसी फर्ग्यूसन की माइक्रो-ड्रामा सीरीज 'मिट्टी के मतवाले' ने भारतीय ट्रैक्टर इंडस्ट्री में बनाई नई राह

पटना। ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड (टैफे) ने 'मिट्टी के मतवाले' नाम की माइक्रो-ड्रामा सीरीज लॉन्च करके ग्राहकों से जुड़ने का एक नया रास्ता अपनाया है। 1960 में चेन्नई में शुरू हुई यह भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निमार्ता कंपनियों में से एक है और बिक्री के लिहाज से भारत में दूसरे नंबर पर है। टैफे हर साल 2.14 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर बेचती है। यह कैंपेन टैफे के मशहूर ट्रैक्टर ब्रांड मैसी फर्ग्यूसन पर आधारित है, जिसने इस शॉर्ट्स सीरीज के जरिए ग्राहकों तक पहुंचने का यह नया अंदाज पेश किया है। इसके साथ टैफे पहली बार मनोरंजन के जरिए अपने ब्रांड की कहानी कह रही है। सीरीज में दमदार कहानी है, ऐसे किरदार हैं जिनमें दर्शक खुद को देख सकें, और ग्रामीण भारत का असली मिजाज है। कंटेंट देखने में डिजिटल मीडिया की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए सीरीज को मोबाइल पर देखने के हिसाब से वर्टिकल फॉर्मेट में छोटे-छोटे एपिसोड में बनाया गया है, जो आपस में जुड़े हैं। इससे दर्शक अपनी रोज की आदत के मुताबिक कहानी देख सकते हैं, और ब्रांड को ऐसी कहानियों के जरिए ग्राहकों तक पहुंचने का मौका मिलता है जो सार्थक हों और अपनी-सी लगें। टैफे ओरिजिनल के रूप में पेश 'मिट्टी के मतवाले' 28 एपिसोड की सीरीज है, जिसमें अभिनेता हार्दिक जोशी मुख्य किरदार आर्य की भूमिका निभा रहे हैं। कहानी एक नौजवान की है, जो परिवार पर अचानक आए संकट के बाद अपने गांव लौटता है। घर वापसी जल्द ही एक बड़े सफर में बदल जाती है। इसमें उसके पिता का अधूरा सपना है, पूरे गांव की उम्मीदें हैं, और ऐसी चुनौतियां हैं जो उसके हौसले और यकीन की परीक्षा लेती हैं। परिवार, रिश्तों, गांव-समाज और कुछ कर दिखाने की चाह के इर्द-गिर्द बुनी यह सीरीज गांव की जिंदगी की सच्चाई, वहां के लोगों की उम्मीदें और उनका अटूट जज्बा दिखाती है। पूरी कहानी में मैसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टर एक सच्चे साथी की तरह साथ चलता है। यह पहल ग्राहकों से जुड़ने के टैफे के उस तरीके को दिखाती है, जो पारंपरिक ब्रांड प्रचार से आगे जाता है। पीढ़ियों से मैसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टर किसान परिवारों में घर के एक अहम सदस्य जैसी जगह रखते आए हैं। खेती की मशीन होने के साथ-साथ ये उनकी रोजी-रोटी, उनके अनुभवों और परिवार के सफर से भी जुड़ गए हैं। 'मिट्टी के मतवाले' इसी रिश्ते को आगे बढ़ाती है। सीरीज में मैसी फर्ग्यूसन को अलग से प्रोडक्ट के तौर पर दिखाने के बजाय गांव की जिंदगी के स्वाभाविक हिस्से की तरह कहानी में पिरोया गया है।

महिला नेतृत्व को मजबूत बनाने पर स्नेहा दुबे पंडित ने रखे महत्वपूर्ण विचार

बेंगलुरु। कॉमनवेल्थ विमेन पार्लियामेंटेरियन्स (CWP) इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस में वसई की विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने के अधिकार को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि महिलाओं को नीतियों के निर्माण और महत्वपूर्ण फैसलों में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर भी मिलना चाहिए। अपने संबोधन में स्नेहा दुबे पंडित ने तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर विशेष जोर दिया। पहली प्राथमिकता : महिला विधायकों के लिए प्रशिक्षण और मेंटरशिप। उन्होंने पहली बार निर्वाचित महिला विधायकों के लिए वर्षभर चलने वाला व्यवस्थित



मेंटरशिप कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इसके माध्यम से महिला जनप्रतिनिधियों को विधायी प्रक्रियाओं की व्यावहारिक जानकारी, अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने और नियमित फॉलोअप के जरिए जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

दूसरी प्राथमिकता : स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को सशक्त बनाना। उन्होंने ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और नगर निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वास्तविक महिला सशक्तिकरण तभी संभव है, जब महिला प्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से निर्णय लें और अपने अधिकारों का प्रभावी इस्तेमाल कर सकें। तीसरी प्राथमिकता : कानून निर्माण और नीतिगत फैसलों में महिलाओं की भागीदारी। उन्होंने विधायी कार्यों, संसदीय एवं विधानसभा समितियों, नीतिगत चचाओं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिला विधायकों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता बताई। इससे महिलाओं के दृष्टिकोण और उनके जमीनी अनुभवों को जनहित की नीतियों में उचित स्थान मिल सकेगा।

स्नेहा दुबे पंडित ने अपने विचारों के माध्यम से स्पष्ट किया कि महिलाओं का सशक्तिकरण केवल संख्या और प्रतिनिधित्व का विषय नहीं है, बल्कि उन्हें अधिकार, अवसर और समाज को प्रभावित करने वाले फैसलों में नेतृत्व करने की स्वतंत्रता देना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब महिलाओं को नेतृत्व करने का पूरा अवसर और अधिकार मिलता है, तो लोकतंत्र अधिक मजबूत होता है, शासन व्यवस्था अधिक समावेशी बनती है और विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचता है।

पराली जलाने के दुष्परिणामों के प्रति किसानों को जागरूक करेगा प्रचार वाहन



जौनपुर (उत्तरशक्ति)। फसल अवशेष (पराली) जलाने से होने वाले नुकसान और मृदा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से 19 नवंबर 2026 को कृषि भवन परिसर से प्रचार वाहन रवाना किया गया। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू (CRM) योजना के तहत उप कृषि निदेशक अश्वनी कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। यह वाहन जनपद के सभी विकास खंडों की न्याय पंचायतों में पहुंचकर किसानों को पराली न जलाने तथा फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन से मृदा स्वास्थ्य को होने वाले लाभों की जानकारी देगा। इस अवसर पर भूमि संरक्षण अधिकारी-द्वितीय कमलजीत सिंह, उप परियोजना निदेशक आत्मा रमेश चन्द्र यादव सहित किसान उपस्थित रहे।

पीयू में अंतर विश्वविद्यालयीय कबड्डी के रोमांचक मुकाबले, क्वार्टर फाइनल जीतने वाली टीमों को मिलेगा ऑल इंडिया का टिकट

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के इनडोर स्टेडियम में चल रही पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालयीय कबड्डी (पुरुष) प्रतियोगिता 2026-27 में गुरुवार को 17 रोमांचक मुकाबले खेले गए। कई मैचों में टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। प्रतियोगिता 21 नवंबर तक चलेगी। पूल-ए में बीएनएम विश्वविद्यालय ने संबलपुर विश्वविद्यालय को 37-26, एसजी गुरु विश्वविद्यालय ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय को 48-39 और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने मगध विश्वविद्यालय को 39-33 से हराया। वहीं आरआईएस ने उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय को 31-30 से पराजित किया। पूल-बी में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर ने पूर्णिया विश्वविद्यालय को



54-13, नॉर्थ लखीमपुर विश्वविद्यालय ने मैट्स विश्वविद्यालय को 37-09 और एसएमके विश्वविद्यालय ने एबीवी विश्वविद्यालय को 34-25 से शिकस्त दी। त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने वर्दमान विश्वविद्यालय को 33-32 से हराया। खेल सचिव डॉ. शेखर सिंह ने बताया कि शुक्रवार को चार क्वार्टर फाइनल सहित आठ टीमों के बीच चार लीग मुकाबले खेले जाएंगे। क्वार्टर फाइनल जीतने वाली चारों टीमें ऑल इंडिया अंतर विश्वविद्यालयीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई करेंगी। प्रतियोगिता के निदेशक सुरेश कुमार सिंह रहे। इस दौरान डॉ. विजय तिवारी, रजनीश सिंह, अशोक सिंह और सतेन्द्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। खेल गतिविधियों का संचालन राजेश सिंह ने किया।

वुशु प्रतियोगिता में साक्षी सिंह ने जीता स्वर्ण, कुलपति ने दी बधाई

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के परिसर की होनहार महिला खिलाड़ी साक्षी सिंह ने अंतरमहाविद्यालयीय वुशु प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 54 किलोग्राम भारवर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एम.एससी. फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की छात्रा साक्षी की इस उपलब्धि से विश्वविद्यालय परिसर में हर्ष का माहौल है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आर.के. सिंह ने साक्षी सिंह को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को मजबूत बनाने का सशक्त माध्यम हैं। विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न



प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना पूरे विश्वविद्यालय परिवार के लिए गर्व की बात है।

कुलपति प्रो. सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय के खिलाड़ी भविष्य में भी अपनी प्रतिभा के बल पर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे।

इस अवसर पर छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. प्रमोद कुमार यादव,परिसर खेल सचिव प्रो. प्रदीप कुमार, डॉ. मनीष कुमार गुप्ता, खेल प्रशिक्षक विजय प्रकाश एवं खेल सहायक रजनीश सिंह ने भी साक्षी सिंह को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

जौनपुर में पहली बार बॉलीवुड फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंची पूरी स्टार कास्ट, मोहम्मद हसन कॉलेज मैदान में उमड़ी भीड़



डॉ. इम्तियाज अहमद

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जौनपुर में पहली बार किसी बॉलीवुड फिल्म के रिलीज से पहले प्रमोशन के लिए फिल्म की पूरी स्टार कास्ट टीम मोहम्मद हसन कॉलेज के मैदान में पहुंची। फिल्म 'गनमास्टर ग्रे' के प्रमोशन के लिए आयोजित कार्यक्रम में युवाओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में बॉलीवुड में सीरियल किसर के नाम से फेमस अभिनेता इमरान हाशमी, अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख व पूर्व आईएएस व अभिनेता अभिषेक सिंह ने शिरकत की। तीनों कलाकारों ने मंच से युवाओं के बीच अपनी फिल्म के बारे में चर्चा की और फिल्म की कहानी, किरदारों और शूटिंग के अनुभवों को साझा किया। इस दौरान इमरान हाशमी ने कहा कि जौनपुर के युवाओं का जोश देखकर बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने सभी से अपील की कि फिल्म को सिनेमाघर में जाकर देखें। जेनेलिया देशमुख ने भी दर्शकों से फिल्म को प्यार देने की अपील की, वहीं अभिषेक सिंह ने कहा कि यह फिल्म एक्शन, इमोशन और मनोरंजन से भरपूर है, जो दर्शकों को जरूर पसंद आएगी।

कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने फैंस के साथ सेल्फी ली, ऑटोग्राफ दिए और युवाओं के सवालों के जवाब भी दिए। मोहम्मद हसन कॉलेज के मैदान में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, युवा और फिल्म प्रेमी मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पहली बार जौनपुर में किसी बॉलीवुड फिल्म की स्टार कास्ट के पहुंचने से पूरे जिले में चर्चा का माहौल है।

जनजातीय आर्थिक उत्थान की दिशा में ऐतिहासिक पहल, पिपरी में पहली बार हुआ SC/ST उद्यमिता जागरूकता



पिपरी, सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। जनजातीय एवं वंचित समाज को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 18 नवंबर को नगर पंचायत पिपरी में पहली बार SC/ST उद्यमिता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। DICCI उत्तर प्रदेश एवं NSSHO के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में करीब 110 उद्यमियों एवं इच्छुक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में DICCI उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मनीष वर्मा एवं NSSHO लखनऊ के इंचार्ज वैभव पाठक प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा जिला उद्योग कार्यालय, बैंकिंग विभाग, NTPC, NCL, रिहंद और हिंडाल्को के अधिकारियों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं, वित्तीय सुविधाओं और स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी दी। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष दिग्विजय प्रताप सिंह, कन्हैया बाबू, नरेश वाल्मीकि, राजेश रावत सहित कई जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन देव मणि सरोज के निर्देशन में वरिष्ठ पत्रकार जी.के. मदान एवं उनकी टीम के सहयोग से हुआ। संचालन अरविंद कुमार ने किया। आयोजकों ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य जनजातीय समाज को केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि उद्यमी और रोजगार सृजक बनाना है।

आशारामजी बापू के उपचार, मोटेरा आश्रम की सुरक्षा और शीघ्र रिहाई की मांग को लेकर आजाद मैदान में शांतिपूर्ण जनआंदोलन

मुंबई। 87 वर्षीय संत श्री आशारामजी बापू के उपचार, मोटेरा आश्रम की सुरक्षा और शीघ्र रिहाई की मांग को लेकर आज मुंबई के आजाद मैदान में शांतिपूर्ण जनआंदोलन किया गया। श्री योग वेदांत सेवा समिति और साधक परिवार की ओर से आयोजित इस आंदोलन में संपूर्ण महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में सनातन धर्म प्रेमी, महिला, वृद्ध और युवा सहभागी हुए। आंदोलन के दौरान प्रशासन को निवेदन दिया गया (आयोजकों के अनुसार बापूजी की गंभीर प्रकृति) आयोजकों का दावा है कि पूज्य बापूजी को 11 गंभीर बीमारियां हैं। हृदय की 3 मुख्य नाड़ियों में 99%, 95% और 85% ब्लॉकेज है और उन्हें कई बार हृदयविकार का झटका आ चुका है। आयोजकों के अनुसार जेल में उन्हें योग्य उपचार नहीं मिल रहा है और उपचार में विलंब खतरनाक हो सकता है। निवेदन में 3 मुख्य मांगें 1. न्यायालय के आदेशानुसार तात्काल सर्वांगीण उपचार व पसंती के प्रशिक्षित निजी



सेवक मिलें,आयोजकों की मांग है कि न्यायालय के आदेशानुसार बापूजी को आरोग्यम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जोधपुर में तात्काल सर्वांगीण उपचार व पसंती के प्रशिक्षित निजी सेवक, त्वरित उपचार और आवश्यक सहायक सुविधा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। आयोजकों ने कहा कि यह किसी विशेषाधिकार की मांग नहीं, बल्कि न्यायालय के आदेशों के पालन और 87 वर्षीय बीमार बंदी को मानवीय आधार पर उपचार देने की विनम्र विनंती है। 2. अहमदाबाद मोटेरा आश्रम को ओलंपिक मैदान के लिए अधिग्रहित न किया जाए, आयोजकों के अनुसार मोटेरा आश्रम तपस्थली है, जो करोड़ों सनातन धर्मियों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। यहां से सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक और महिला उत्थान जैसे कई सेवा कार्य चलाए जाते हैं। इस पवित्र तपस्थली को ओलंपिक के खेल मैदान के लिए अधिग्रहित न किया जाए। 3. केस की त्वरित निष्पक्ष जांच व शीघ्र रिहाई आयोजकों का दावा है कि बापूजी पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नहीं है, मेडिकल जांच में कोई सबूत नहीं है। निष्पक्ष उइक जांच हो और बापूजी को शीघ्र निर्दोष रिहाई मिले। साथ ही आयोजकों ने आरोप लगाया कि केस में उम्र संबंधी दस्तावेजों की पड़ताल किए बिना ढडउरड कानून का दुरुपयोग हो रहा है। आंदोलन में उपस्थित सत्येंद्र शर्मा (महाराष्ट्र संचालन),आशुतोष झा(सोशल मीडिया प्रभावक),अभय वर्तक (हिंदू सनातन संस्था,राष्ट्रीय प्रवक्ता),शंकराचार्य त्रिकाल भवंता सरस्वती, गौतम रावरिया (बजरंग दल,कोकण प्रांत),बाबुभाई (राष्ट्रीय स्वयंसेवक),एडवोकेट संतोष दुबे, ह.भ.प. भगवान महाराज आव्हाड (वारकरी संप्रदाय), युवा वारकरी ह.भ.प. श्री ईश्वरजी महाराज नागरे और अन्य हिंदू संगठन, श्री योग वेदांत सेवा समिति और युवा सेवा संघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हजारों लोगों ने किए हस्ताक्षर* आंदोलन में हजारों लोगों ने निवेदन पर हस्ताक्षर किए। यह निवेदन मंत्रालय, कलेक्टर और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को दिया गया। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। हमारी मांग सिर्फ यही है तात्काल सर्वांगीण उपचार, मोटेरा आश्रम की सुरक्षा, निष्पक्ष जांच और शीघ्र रिहाई। आवश्यकता पड़ने पर तीव्र राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी किया जाएगा।

अँड. ट्यूलिप ब्रेन मिरांडा को जन्मदिन पर दी गईं हार्दिक शुभकामनाएं



मुंबई। बुधवार को वार्ड क्रमांक 90 की नगरसेविका एवं मुंबई महिला कांग्रेस अध्यक्ष अँड. ट्यूलिप ब्रेन मिरांडा को उनके जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर कालिना, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई स्थित उनके जनसंपर्क कार्यालय में समाजसेवक एवं समाजसेविकाओं ने पहुंचकर शॉल और पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी तथा उनके सुखद एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। इस मौके पर समाजसेविका श्रद्धा गोरगे, सुखबिंदर सिंह (लाला भाई) सहित वार्ड के अन्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने अँड. ट्यूलिप ब्रेन मिरांडा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। वहीं, अँड. ट्यूलिप ब्रेन मिरांडा ने उपस्थित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और उनके लिए अल्पाहार की व्यवस्था कर आत्मीय स्वागत किया। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।

मुंबई लोकल में वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात, चर्चगेट छोर से 7वां डिब्बा होगा सीनियर सिटीजन्स के लिए आरक्षित

-लालशेखर सिंह

मुंबई। (उत्तरशक्ति) मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले लाखों वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है। पश्चिम रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग डिब्बे की मांग को मंजूरी दे दी है। रेलवे बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस निर्णय से बुजुर्ग यात्रियों को भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेनों में अधिक सुरक्षित और आरामदायक सफर की सुविधा मिलने की उम्मीद है। पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय की वाणिज्य शाखा ने 14 मई 2025 को लिखित रूप में इसकी पुष्टि की। यह कार्रवाई जीवन



संध्या सीनियर सिटीजन्स ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री विनय कुमार खेमका द्वारा 9 अक्टूबर 2024 को भेजे गए पत्र के बाद हुई। पश्चिम रेलवे के अनुसार, नॉन-एसी ईएमयू लोकल ट्रेनों में मौजूदा लगेज कम्पार्टमेंट में से चर्चगेट छोर से सातवें डिब्बे को वरिष्ठ नागरिकों के कम्पार्टमेंट में परिवर्तित किया जाएगा। रेलवे ने स्पष्ट किया कि यह नीतिगत विषय होने के कारण प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। पश्चिम और मध्य रेलवे की कुछ लोकल ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी व्यवस्था पहले से शुरू की जा चुकी है। इस सुविधा को आगामी दो वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस उपलब्धि के पीछे जीवन संध्या सीनियर सिटीजन्स ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष श्री विनय कुमार खेमका का वर्षों का निरंतर प्रयास रहा है। उन्होंने वर्ष 2011 में जीवन संध्या सीनियर सिटीजन्स ट्रस्ट की स्थापना की थी। ट्रस्ट की स्थापना के बाद से ही वे वरिष्ठ नागरिकों को मुंबई लोकल में यात्रा के दौरान होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए लगातार रेल अधिकारियों से मुलाकात करते रहे और पत्राचार के माध्यम से उनकी समस्याएं उठाते रहे।

वर्ष 2016 में विनय कुमार खेमका द्वारा उठाई गई समस्याओं का संज्ञान लेते हुए रेल विभाग ने मुंबई लोकल ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए छह सीटें आरक्षित की थीं। हालांकि, यात्रियों की संख्या और जरूरतों को देखते हुए यह व्यवस्था अपर्याप्त साबित हो रही थी।

इसके बाद खेमका ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग डिब्बे की मांग को लेकर दिल्ली से मुंबई तक रेलवे के विभिन्न अधिकारियों और संबंधित विभागों के समक्ष लगातार प्रयास जारी रखे। आखिरकार उनकी वर्षों की मेहनत और निरंतर प्रयासों को सफलता मिली।

इस उपलब्धि पर जीवन संध्या सीनियर सिटीजन्स ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री विनय कुमार खेमका ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सभी वरिष्ठ नागरिकों के वर्षों के प्रयास और प्रतीक्षा का परिणाम है। उन्होंने रेलवे प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रेलवे ने बुजुर्गों की परेशानियों को समझते हुए उनके हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वरिष्ठ नागरिकों के हित में लिए गए इस निर्णय पर सदुरु फाउंडेशन ट्रस्ट के चेयरमैन गणेश अग्रवाल, छोटा चेतन, विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रमुख सदस्य अलख नारायण चौबे, समाजसेवी रमेश चौबे, दुर्गा यादव और प्रशांत चारी सहित अनेक लोगों ने विनय कुमार खेमका को बधाई दी। साथ ही उन्होंने रेलवे प्रशासन के अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। यह निर्णय मुंबई के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा साबित हो सकता है। अलग कम्पार्टमेंट की व्यवस्था से बुजुर्ग यात्रियों को भीड़भाड़ के बीच होने वाली परेशानियों से राहत मिलने और उनकी रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनने की उम्मीद है।

रामकथा के बहाने बाहुबलियों की गोलबंदी...

-सुरेश गांधी

कुंडा (प्रतापगढ़)। रामकथा की चौपाइयां गूंज रही थीं, मंच पर सनातन और हिंदुत्व का उद्घोष हो रहा था, लेकिन इस धार्मिक समागम के बीच सियासत की एक अलग ही तस्वीर आकार ले रही थी। एक ओर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का प्रभावशाली धार्मिक मंच, दूसरी ओर उसके सूत्रधार राजा भैया और सामने उत्तर प्रदेश की राजनीति के कई ऐसे चेहरे, जिनकी पहचान अपने-अपने क्षेत्र में रसूख, दबदबे और प्रभावशाली राजनीतिक पकड़ से रही है। सबसे चौंकाने वाला दृश्य तब सामने आया, जब कभी एक-दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले चेहरे भी एक ही मंच और सोफे पर नजर आए। कुंडा की इस रामकथा ने इसीलिए धार्मिक आयोजन की सीमा लांघकर 2027 की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। जौनपुर के पूर्व सांसद



धनंजय सिंह, वाराणसी के चर्चित पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह और चंदौली के विधायक सुशील सिंह की एक साथ मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा। पूर्वांचल की राजनीति में इन नामों के साथ प्रभाव, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और क्षेत्रीय ताकत की अलग-अलग कहानियां जुड़ी रही हैं। ऐसे चेहरों का राजा भैया के आयोजन में एक साथ दिखाई देना सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार से आगे का दृश्य बन गया। इसके अलावा पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, संजीव बालियान, झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और अन्य राजनीतिक हस्तियों की मौजूदगी ने आयोजन का दायरा और व्यापक कर दिया। कुंडा की इस जमघट का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जिन नेताओं की राजनीतिक यात्राएं अलग-अलग रास्तों से आगे बढ़ी हैं, वे भी एक धार्मिक मंच पर साथ बैठ सकते हैं। इसे किसी राजनीतिक समझौते की घोषणा नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि इसने वर्षों से बनी दूरी और प्रतिद्वंद्विता की रेखाओं को एक तस्वीर में धुंधला कर दिया। राजा भैया ने अपने आयोजन के जरिए केवल बड़ी रामकथा नहीं कराई, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रभावशाली राजनीतिक चेहरों को एक छत के नीचे लाने की क्षमता भी दिखाई। राजनीतिक हलकों में इन चेहरों को अक्सर बाहुबली राजनीति, क्षेत्रीय रसूख और प्रभावशाली सामाजिक आधार के संदर्भ में देखा जाता रहा है। हालांकि किसी व्यक्ति की पहचान केवल इस विशेषण से तय नहीं होती, फिर भी इन नेताओं की राजनीतिक हैसियत और उनके समर्थक वर्ग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि कुंडा में हुआ यह जुटान अब सियासी चर्चा का विषय है। इस आयोजन की एक और उल्लेखनीय परत क्षत्रिय पृष्ठभूमि से जुड़े प्रभावशाली चेहरों की मौजूदगी है। राजा भैया से लेकर पूर्वांचल के कई चर्चित नेताओं तक, इस जमावड़े में ऐसे नाम दिखाई दिए जिनकी सामाजिक पहचान और क्षेत्रीय राजनीतिक प्रभाव की अपनी अहमियत है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले क्षत्रिय नेतृत्व और प्रभावशाली क्षेत्रीय चेहरों के बीच संपर्क का कोई नया सिलसिला आकार ले रहा है? उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में जातीय समीकरण कभी अकेले चुनाव नहीं जिताते, लेकिन वे राजनीतिक रणनीति को दिशा जरूर देते हैं। क्षत्रिय समाज का परंपरागत राजनीतिक प्रभाव, अलग-अलग दलों में उसकी भागीदारी और स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली नेताओं की पकड़ चुनावी गणित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। ऐसे में एक ही मंच पर इस पृष्ठभूमि के कई चर्चित चेहरों का दिखना राजनीतिक संकेतों की तलाश को स्वाभाविक बनाता है। क्या यह महज संयोग है या आने वाले चुनाव से पहले सामाजिक संपर्कों और राजनीतिक संवाद की कोई नई जमीन तैयार हो रही है? इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में राजा भैया हैं। कुंडा की राजनीति में उनका प्रभाव किसी परिचय का मोहताज नहीं। सात बार के विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष के रूप में उनकी अपनी राजनीतिक पहचान है। इस आयोजन में अलग-अलग दलों, क्षेत्रों और राजनीतिक पृष्ठभूमियों के नेताओं की उपस्थिति ने उनकी मेजबानी को भी राजनीतिक अर्थ दे दिया है। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का मंच से यह कहना कि राजा भैया का दबदबा पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, इस माहौल को और चर्चा में ले आया। धीरेंद्र शास्त्री ने भी राजा भैया की व्यवस्था और बेबाकी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हर जिले में राजा भैया जैसा व्यक्ति हो तो कोई कथा नहीं रोक पाएगा।

पुलिस के मामलों में दोषसिद्धि कम होने पर डीजीपी नाराज

मुंबई। महाराष्ट्र में मुंबई सहित राज्य के कई पुलिस थानों में दर्ज आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि (कन्विक्शन) का प्रतिशत कम होने पर पुलिस महानिदेशक ने नाराजगी जताई है। इस संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि आने वाले समय में दोषसिद्धि का प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। इस संबंध में शहर और रेलवे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। बैठक में साइबर अपराधों पर नियंत्रण को लेकर भी विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक के साथ प्रत्येक सप्ताह सूचनाओं का आदान-प्रदान करने और साइबर अपराधों से निपटने के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, दोषसिद्धि का प्रतिशत बढ़ाने के साथ-साथ बरी होने वाले आरोपियों के मामलों का आंकड़ा संकलित कर उनमें सुधार लाने पर भी जोर दिया गया। पुलिस महानिदेशक ने अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) को सभी घटक प्रमुखों के साथ समन्वय स्थापित कर दोषसिद्धि की दर में सुधार लाने के निर्देश दिए। आगामी त्योहारों और महापुरुषों की जयंती के मद्देनजर कड़े सुरक्षा इंतजाम करने तथा आंदोलनों, सूखे और पानी की किल्लत के कारण कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो, इसका विशेष ध्यान रखने को कहा गया। आगामी 7 दिसंबर से नागपुर में शुरू होने वाले शीतकालीन विधानसभा सत्र को देखते हुए शासन को प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी तत्काल अद्यतन करने के निर्देश भी दिए गए। अधिवेशन से पहले तैयारी बैठकें आयोजित कर लंबित ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, आश्वासनों और प्रश्नोत्तरों से संबंधित जानकारी जल्द से जल्द संकलित करने को कहा गया। वहीं, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 56 के तहत पिछले सप्ताह सभी पुलिस घटकों से मांगी गई जानकारी और संबंधित प्रमाणपत्रों की भी समीक्षा की गई। बैठक में बीट स्तर पर गश्त बढ़ाने, आरोपपत्र (चार्जशीट) जल्द दाखिल करने और उन्हें पुलिस महानिदेशक कार्यालय भेजने के निर्देश दिए गए।

मैटकेयर हॉस्पिटल पटना के डॉक्टरों ने साझा किए हाई रिस्क प्रेगनेंसी के तीन मामले, गर्भ में ही हुआ शिशु का इलाज



पटना। जन्म के समय सिर्फ 693 ग्राम वजन वाली एक बच्ची, जो एक लीटर के दूध के पैकेट से भी हल्की थी, मैटकेयर मैटरनिटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, पटना के एनआईसीयू में 82 दिन इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौट गई है। मैटकेयर पटना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके साथ दो अन्य हाई-रिस्क प्रेगनेंसीज के मामले में सफलता प्राप्त होने के बारे में जानकारी दी। मैटकेयर पटना के हेड डॉ. दयानिधि कुमार ने कहा कि हाई-रिस्क प्रेगनेंसी में हर समय निगरानी आवश्यक है। इन केसेज को मैटकेयर पटना की पूरी टीम द्वारा संभाला गया, जिसमें डॉ. श्वेता शिल्पी, डॉ. ज्योत्सना, डॉ. अमिश कुमार, डॉ. सोनू कुमार, डॉ. अंजलि कुमारी, डॉ. ज्योति डिंकर, डॉ. अपर्णा, डॉ. अतुल, डॉ. अनुश्री, डॉ. ब्यूटी तिवारी के साथ साथ सारे स्टाफ शामिल हैं, जिन्होंने एक टीम की तरह दिन-रात काम किया। मैटकेयर पटना की स्त्री रोग एवं प्रसूति कंसल्टेंट तथा फेटल मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. श्वेता शिल्पी ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को कभी भी जांच करवाने से पीछे नहीं हटना चाहिए और सूजन, तेज सिरदर्द या बच्चे की हलचल कम होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वहीं मैटकेयर पटना की सीनियर कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजिस्ट डॉ. ज्योत्सना ने कहा कि 693 ग्राम के वजन वाले बच्चे को हर चीज सांस लेने, दूध पीने और संक्रमण से लड़ने के लिए मदद की आवश्यकता होती है, ऐसे में समय पर उपचार से सफलता मिल सकती है। मैटकेयर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. सोनू कुमार ने कहा कि समय से पहले जन्मे बच्चों को विकास, टीकाकरण, आंखों और सुनने की क्षमता के लिए नियमित फॉलो-अप की जरूरत होती है। हम हर कदम पर परिवारों के साथ रहते हैं। डॉ. अमिश कुमार ने कहा कि मैटकेयर अस्पताल में लेवल थ्री एनआईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू, 24 घंटे प्रसूति एवं नवजात आपातकालीन सेवाएं, एनआईसीयू ऑन व्हील्स एंबुलेंस, 3डी / 4डी और डॉपलर स्कैन के साथ फेटल मेडिसिन तथा पेनलेस डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है।

सड़कों पर सुर्खियाँ: कैसे मोटरस्पोर्ट भारत के विकास को गति दे सकता है

नवी मुंबई। जैसे-जैसे भारत में मोटरस्पोर्ट की लोकप्रियता बढ़ रही है, स्ट्रीट रेसिंग (शहर की सड़कों पर होने वाली रेस) इस खेल को शहरी दर्शकों के करीब लाने का एक अवसर देती है। साथ ही, इससे पर्यटन, आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी), तकनीक और रोजगार के क्षेत्रों में अवसरों का एक बड़ा तंत्र भी तैयार होता है। 5-6 दिसंबर 2026 को नवी मुंबई की सड़कों पर होने वाला इंडियन रेसिंग फेस्टिवल (IRF) का आगामी नाइट-रेस फिनाले इसी संभावना को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे रेसिंग के नए प्रारूप शहरी जगहों को खेल और मनोरंजन के केंद्र में बदल सकते हैं। रेस ट्रैक पर होने वाले रोमांच के अलावा, मोटरस्पोर्ट आयोजनों से कई क्षेत्रों के पेशेवरों और व्यवसायों को जुड़ने का मौका मिलता है। इनमें इवेंट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग, ब्रॉडकास्टिंग और हॉस्पिटैलिटी शामिल हैं। ऐसे आयोजन शहरों को बड़े स्तर के खेल आयोजनों की मेजबानी करने की अपनी क्षमता बढ़ाने में भी मदद करते हैं, जिससे स्थानीय व्यवसायों और सेवा प्रदाताओं के लिए नए अवसर बनते हैं। गोवा एसेस जेए रेसिंग के मालिक जॉन अब्राहम का मानना है कि स्ट्रीट रेसिंग भारत में मोटरस्पोर्ट की संस्कृति को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। अब्राहम ने कहा, मोटरस्पोर्ट में भारत के खेल जगत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने की क्षमता है। स्ट्रीट रेसिंग इस खेल को शहरों में लाने और उन दर्शकों से जोड़ने का एक रोमांचक अवसर देती है, जिन्होंने शायद पहले कभी इसका अनुभव नहीं किया हो। इससे जागरूकता बढ़ाने में मदद मिल सकती है और साथ ही उन तकनीकों, सटीकता व टीमवर्क को दिखाया जा सकता है जो मोटरस्पोर्ट को खास बनाते हैं। स्पीड डीमन्स दिल्ली के मालिक अर्जुन कपूर ने सुलभ और आकर्षक खेल अनुभव बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। कपूर ने कहा, किसी भी खेल के बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि लोगों को उससे जुड़ने के अवसर मिलें। स्ट्रीट सर्किट और नवी मुंबई में प्रस्तावित रेस जैसे आयोजन प्रशंसकों को खेल के करीब ला सकते हैं और उन्हें एक अलग खेल अनुभव दे सकते हैं, जिससे मोटरस्पोर्ट पारंपरिक रेसिंग स्थानों से निकलकर शहर के बीचोंबीच पहुँचता है। ऐसे आयोजन शहरी विकास में भी योगदान दे सकते हैं, स्थानीय व्यवसायों के लिए अवसर बना सकते हैं और मेजबान शहर को वैश्विक खेल मानचित्र पर ला सकते हैं, जिससे मोटरस्पोर्ट को बड़े दर्शक वर्ग तक पहुँचाने में मदद मिलती है। कोलकाता रॉयल टाइगर्स के मालिक सौरव गांगुली ने इस खेल के आसपास एक टिकाऊ तंत्र विकसित करने के महत्व पर जोर दिया।

पीएनबी ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर युवा केंद्रित नेक्स्ट जेन डिजिटल बैंकिंग शाखा का उद्घाटन किया



मुंबई। सार्वजनिक क्षेत्र में भारत के अग्रणी बैंकों में से एक पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर अपनी अत्याधुनिक 'नेक्स्ट जेन बैंकिंग शाखा' का उद्घाटन किया। इसे विशेष रूप से एक युवा-केंद्रित डिजिटल हब के रूप में तैयार किया गया है, जो युवा ग्राहकों, वरिष्ठ नागरिकों, एचएनआई और एनआरआई को 24ग्7 बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है। इस शाखा का उद्घाटन वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) की संयुक्त सचिव श्रीमती शालिनी पंडित, पीएनबी के एमडी एवं सीईओ अशोक चंद्र, वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव दिवेश सेहरा, आईएएस, पीएनबी के कार्यकारी निदेशक डी. सुरेंद्रन, पीएनबी के सीवीओ राघवेंद्र कुमार, और दिल्ली के अंचल प्रबंधक राजेश भौमिक के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों, ग्राहकों और अन्य विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। इस शाखा में उन्नत डिजिटल साल्यूशन्स उपलब्ध हैं, जिनमें मल्टीफंक्शनल कियोस्क (एमएफके), तत्काल खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी (वीकेवाईसी) युक्त इंटरनेट कियोस्क, बल्क नोट एक्सेप्टर (बीएनए), स्मॉल वैल्यू डिस्पेंसिंग मशीन (एसवीडीएम), कतार प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) और एक समर्पित एनआरआई लाउंज शामिल हैं। श्रीमती शालिनी पंडित. संयुक्त सचिव, डीएफएस ने इस दूरदर्शी पहल के लिए पीएनबी की सराहना की और ग्राहकों की सुविधा तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों द्वारा डिजिटल परिवर्तन में और तेजी लाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सर्वोत्तम ग्राहक सेवा प्रदान करना बैंकों का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए और तकनीक का लाभ उठाना इस दिशा में मददगार हो सकता है।

उपस्थित समूह को संबोधित करते हुए पीएनबी के एमडी एवं सीईओ अशोक चंद्र ने सभी व्यावसायिक मापदंडों पर बैंक की निरंतर प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस सफलता का श्रेय मुख्य परिचालन मापदंडों में मजबूत प्रदर्शन और सभी हितधारकों के अटूट विश्वास को दिया। बैंक के विजन पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यह नए रूप में तैयार की गई शाखा, कोर बैंकिंग की मजबूती को डिजिटल उत्कृष्टता के साथ जोड़कर और यह सुनिश्चित करके कि उन्नत डिजिटल पहल ग्रामीण तथा बैंकिंग सेवा से वंचित अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने की पीएनबी की प्रतिबद्धता को दशार्ती है। डीएफएस के संयुक्त सचिव दिवेश सेहरा, आईएएस ने पीएनबी के नेतृत्व वाली इस पहल की प्रशंसा की और डिजिटल अपनाने में तेजी लाने तथा बैंकिंग सेवाओं तक ग्राहकों की पहुंच में सुधार करने के लिए विभिन्न स्थानों पर ऐसी और अधिक 'नेक्स्ट जेन' शाखाएं स्थापित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। कार्यक्रम का समापन पीएनबी के कार्यपालक निदेशक डी. सुरेंद्रन के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने गणमान्य व्यक्तियों, डीएफएस अधिकारियों, ग्राहकों और कर्मचारियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के लिए आभार व्यक्त किया।

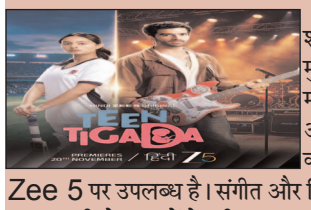
रिपब्लिकन आंदोलन के अस्तित्व और एकता के लिए आंबेडकरी संगठनों की चिंतन बैठक



मुंबई,घाटकोपर। रिपब्लिकन आंदोलन के अस्तित्व और मजबूती को बनाए रखने के उद्देश्य से घाटकोपर स्थित माता रमाबाई आंबेडकर नगर में विभिन्न आंबेडकरी संगठनों के पदाधिकारियों की चिंतन बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने तथा रिपब्लिकन आंदोलन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि रिपब्लिकन आंदोलन का इतिहास संघर्ष और एकता का इतिहास रहा है। जब-जब इस आंदोलन के अस्तित्व पर संकट आया, तब-तब समाज के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आगे आकर एकजुट होकर संघर्ष किया और आंदोलन को मजबूत बनाए रखा। वर्तमान समय में भी रिपब्लिकन आंदोलन के अस्तित्व की रक्षा के लिए आंबेडकरी विचारधारा से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक मंच पर आने की आवश्यकता है।

माता रमाबाई आंबेडकर नगर स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित इस सर्वदलीय चिंतन बैठक की जानकारी बैठक के निमंत्रक नारायणराव बागडे ने दी। बैठक में नानासाहेब इंदिसे, तानसेन ननावरे, अण्णासाहेब कटारे, सांगर संसारे, उत्तमराव गायकवाड, नितिन मोरे, सोपान पवार, रवि शेंडे, मनोज गायकवाड, दयानंद मस्के, दिनेश भंडागे, देवेंद्र बागडे सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मुंबई के शिवाजी पार्क में रिपब्लिकन एकता संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा नागपुर में आयोजित होने वाले विधानसभा के शीतकालीन अधिवेशन के दौरान आगामी 16 दिसंबर को विभिन्न जनहित के मुद्दों को लेकर संयुक्त मोर्चा निकालने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने रिपब्लिकन आंदोलन की एकता और मजबूती के लिए मिलकर काम करने का संकल्प व्यक्त किया।

महत्वाकांक्षाओं और जिंदगी के उतार-चढ़ाव को बयां करती दिल छू लेने वाली कहानी तीन तिगाड़ा अब हिंदी Zee5 पर देखें



ठाणे। प्यार, सपने और जिंदगी शायद ही कभी हमारी सोच के मुताबिक चलते हैं। युवा प्रेम, महत्वाकांक्षाओं और जिंदगी के अनपेक्षित मोड़ों को एक साथ पेश करने वाली तीन तिगाड़ा अब हिंदी Zee 5 पर उपलब्ध है। संगीत और क्रिकेट की दुनिया की पृष्ठभूमि पर बनी यह कहानी दो युवाओं के जीवन पर आधारित है, जो प्यार और अपने सपनों को पूरा करने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अचानक उनके सामने एक ऐसी स्थिति आ जाती है, जो उनकी जिंदगी बदल देती है और भविष्य को लेकर उनकी अब तक की सारी सोच को चुनौती देती है। इस सीरीज में प्रसन्ना बिष्ट, दानेश रजवी, अर्चिका अरोड़ा, समर्थ मेहता और ग्रुशा कपूर अहम भूमिकाओं में हैं। तीन तिगाड़ा का निर्माण स्ट्रीटलैंप मीडिया एंटरटेनमेंट एलएलपी और आई स्क्रीम ड्रीम्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। इस सीरीज की कहानी के केंद्र में अस्मानी और मनन हैं, जिनकी भूमिका क्रमशः प्रसन्ना बिष्ट और दानेश रजवी ने निभाई है। दोनों अपने रिश्ते के साथ-साथ अपने-अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच अचानक अस्मानी के गर्भवती होने की खबर उनकी जिंदगी बदल देती है और उनकी प्रेम कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ उनके सपने और रिश्ता हैं, तो दूसरी तरफ उन पर आई नई जिम्मेदारियां। ऐसे में सवाल उठता है कि इस युवा जोड़े की जिंदगी में आगे क्या होगा और यह बड़ा बदलाव उनके भविष्य को किस तरह बदल देगा। युवा प्रेम, हल्के-फुल्के पलों और भावनाओं से भरे उतार-चढ़ाव को समेटे तीन तिगाड़ा प्यार, महत्वाकांक्षाओं और बड़े होने के साथ आने वाले फैसलों की कहानी पेश करती है। यह सीरीज अब केवल Zee 5 पर स्ट्रीम हो रही है। तीन तिगाड़ा की खास बात है कि यह युवा प्रेम और जिंदगी में अचानक आने वाले बदलावों को बेहद सहज और वास्तविक तरीके से दिखाती है। प्यार, हास्य और भावनाओं से भरे पलों के जरिए यह सीरीज सपनों को पूरा करने के उत्साह के साथ रिश्तों को निभाने और अचानक आने वाली जिम्मेदारियों को संभालने की कहानी पेश करती है। मुख्य किरदारों और उनके अलग-अलग सपनों के जरिए यह कहानी दिखाती है कि जिंदगी में आने वाले बड़े बदलाव किस तरह रिश्तों की परीक्षा लेते हैं, हमारी प्राथमिकताएं बदल देते हैं और बड़े होने के अनुभव को पूरी तरह नया रूप दे देते हैं।

मैसी फर्ग्यूसन की माइक्रो-ड्रामा सीरीज 'मिट्टी के मतवाले' ने भारतीय ट्रैक्टर इंडस्ट्री में बनाई नई राह

पटना। ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड (टैफे) ने 'मिट्टी के मतवाले' नाम की माइक्रो-ड्रामा सीरीज लॉन्च करके ग्राहकों से जुड़ने का एक नया रास्ता अपनाया है। 1960 में चेन्नई में शुरू हुई यह भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निमार्ता कंपनियों में से एक है और बिक्री के लिहाज से भारत में दूसरे नंबर पर है। टैफे हर साल 2.14 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर बेचती है। यह कैंपेन टैफे के मशहूर ट्रैक्टर ब्रांड मैसी फर्ग्यूसन पर आधारित है, जिसने इस शॉर्ट्स सीरीज के जरिए ग्राहकों तक पहुंचने का यह नया अंदाज पेश किया है। इसके साथ टैफे पहली बार मनोरंजन के जरिए अपने ब्रांड की कहानी कह रही है। सीरीज में दमदार कहानी है, ऐसे किरदार हैं जिनमें दर्शक खुद को देख सकें, और ग्रामीण भारत का असली मिजाज है। कंटेंट देखने में डिजिटल मीडिया की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए सीरीज को मोबाइल पर देखने के हिसाब से वर्टिकल फॉर्मेट में छोटे-छोटे एपिसोड में बनाया गया है, जो आपस में जुड़े हैं। इससे दर्शक अपनी रोज की आदत के मुताबिक कहानी देख सकते हैं, और ब्रांड को ऐसी कहानियों के जरिए ग्राहकों तक पहुंचने का मौका मिलता है जो सार्थक हों और अपनी-सी लगें। टैफे ओरिजिनल के रूप में पेश 'मिट्टी के मतवाले' 28 एपिसोड की सीरीज है, जिसमें अभिनेता हार्दिक जोशी मुख्य किरदार आर्य की भूमिका निभा रहे हैं। कहानी एक नौजवान की है, जो परिवार पर अचानक आए संकट के बाद अपने गांव लौटता है। घर वापसी जल्द ही एक बड़े सफर में बदल जाती है। इसमें उसके पिता का अधूरा सपना है, पूरे गांव की उम्मीदें हैं, और ऐसी चुनौतियां हैं जो उसके हौसले और यकीन की परीक्षा लेती हैं। परिवार, रिश्तों, गांव-समाज और कुछ कर दिखाने की चाह के इर्द-गिर्द बुनी यह सीरीज गांव की जिंदगी की सच्चाई, वहां के लोगों की उम्मीदें और उनका अटूट जज्बा दिखाती है। पूरी कहानी में मैसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टर एक सच्चे साथी की तरह साथ चलता है। यह पहल ग्राहकों से जुड़ने के टैफे के उस तरीके को दिखाती है, जो पारंपरिक ब्रांड प्रचार से आगे जाता है। पीढ़ियों से मैसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टर किसान परिवारों में घर के एक अहम सदस्य जैसी जगह रखते आए हैं। खेती की मशीन होने के साथ-साथ ये उनकी रोजी-रोटी, उनके अनुभवों और परिवार के सफर से भी जुड़ गए हैं। 'मिट्टी के मतवाले' इसी रिश्ते को आगे बढ़ाती है। सीरीज में मैसी फर्ग्यूसन को अलग से प्रोडक्ट के तौर पर दिखाने के बजाय गांव की जिंदगी के स्वाभाविक हिस्से की तरह कहानी में पिरोया गया है।

किआ इंडिया की फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी कारों को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स

मुंबई। देश की प्रमुख मास-प्रीमियम कार निमार्ता कंपनी किआ इंडिया ने सितंबर 2026 में लॉन्च के बाद से अपनी फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी कारों–किआ कैरेंस सीएनजी और किआ कैरेंस क्लैविस सीएनजी–की 6,200 होलसेल यूनिट्स का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि किफायती, व्यावहारिक और आधुनिक फीचर्स से लैस फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी वाहनों के प्रति ग्राहकों की बढ़ती पसंद को दशार्ती है। इसके साथ ही, किआ के 'एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम' के तहत तीन साल बाद कार की कीमत का 75% तक वापस मिलने की गारंटी भी दी जा रही है। इस सफलता पर किआ इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स श्री अतुल सूद ने कहा, कैरेंस क्लैविस सीएनजी और कैरेंस सीएनजी की 6,200 होलसेल यूनिट्स का आंकड़ा पार करना हमारे लिए बेहद उत्साहजनक है और बाजार में हमारी सीएनजी कारों की बढ़ती स्वीकार्यता का प्रमाण है। ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुरूप विभिन्न इंजन विकल्प देना हमारी प्राथमिकता है। हम अपने पोर्टफोलियो को ऐसी पैसा वसूल गाड़ियों से मजबूत करते रहेंगे, जिनमें रोजमर्रा के इस्तेमाल की आसानी, आराम और आधुनिक तकनीक का मेल हो। G1.5 6MT पावरट्रेन पर आधारित इन दोनों मॉडलों में फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट, 60 लीटर का टैंक, विशेष रूप से ट्यून किया गया इंजन और बदली हुई सस्पेंशन सेटिंग दी गई है। इनमें अलग फ्यूल स्विच और 4.2 इंच का कलर टीएफटी एमआईडी (जो बची हुई सीएनजी की रेंज दिखाता है) के साथ तीसरी पंक्ति के यात्रियों के बेहतर आराम के लिए रिक्लाइनिंग बैकरेस्ट फ्रेम दिया गया है।

गंगा की लहरों पर दीपों की चादर, आकाश में शिव का डमरू



वाराणसी। कार्तिक की पूर्णिमा पर जब सांझ की पहली लालिमा गंगा की लहरों में उतरने लगेगी, तब काशी के घाटों पर आस्था के दीप एक-एक कर जगमगाने लगेंगे। अर्द्धचंद्राकार गंगा तट पर टिमटिमाते लाखों दीपों की लौ जब जल में अपना प्रतिबिंब रचेगी तो धरती और आकाश के बीच काशी का एक अलौकिक संसार आकार लेगा। इस बार यह दृश्य और विराट होगा। 24 नवंबर को देव दीपावली पर काशी में 21 लाख से अधिक दीप प्रज्ज्वलित करने की तैयारी है। इनमें 11 लाख दीप प्रशासन की ओर से और 10 लाख दीप काशी के स्वयंसेवी संगठनों, मंदिरों, देव दीपावली समितियों और अन्य सामाजिक-धार्मिक संस्थाओं की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे। दीपों की इस विराट श्रृंखला के बीच गंगा की लहरों पर महाआरती की आभा होगी तो आसमान में 2100 स्वदेशी ड्रोन भगवान शिव के तांडव, मां गंगा के अवतरण और काशी की आध्यात्मिक विरासत के दृश्य उकेरेंगे। पिछले तीन-चार वर्षों से देव दीपावली को अधिक व्यापक और भव्य स्वरूप देने की कोशिशों को इस बार गंगा के दोनों किनारों तक विस्तार देने की तैयारी है। गंगा पार की रेती को भी आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा, ताकि चंदौली की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी उत्सव का वैसा ही अनुभव मिले। इससे घाटों के एक ही हिस्से पर भीड़ का दबाव कम करने और श्रद्धालुओं को गंगा के दोनों तटों से दीपोत्सव का विहंगम दृश्य दिखाने की मंशा है। प्रशासन का जोर आयोजन की भव्यता के साथ यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा पर भी है। इस बार देव दीपावली का एक बड़ा आकर्षण 2100 स्वदेशी ड्रोन का शो होगा। करीब 15 मिनट की इस प्रस्तुति में आसमान पर रोशनी से भगवान शिव, महेश्वर सूत्र, संगीतमय शिव तांडव, मां गंगा के धरती पर अवतरण, काशी विश्वनाथ मंदिर और मां विशालाक्षी की आकृतियां उकेरी जाएंगी। विशेष थ्री-डी एनिमेशन, संगीत और हिंदी वॉयस ओवर के जरिए पौराणिक प्रसंगों को जीवंत करने की तैयारी है। करीब 15 विशेष फॉर्मेशन में होने वाला यह प्रदर्शन काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत करेगा। ड्रोन शो के साथ लेजर शो और प्रोजेक्शन मैपिंग भी आकर्षण बढ़ाएंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार शाम 7:20 से 7:45 बजे तक चेत सिंह घाट पर 25 मिनट का लेजर और प्रोजेक्शन शो होगा। इसके बाद रात आठ बजे से करीब 15 मिनट तक ड्रोन शो प्रस्तावित है। ग्रीन आतिशबाजी रात 8:30 से 8:40 बजे तक काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार के सामने होगी। आतिशबाजी के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों और संबंधित विभागों की अनुमति सुनिश्चित की जाएगी। ड्रोन उड़ान के लिए भी विशेष जोन निर्धारित होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित क्षेत्र में निजी ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी, ताकि तकनीकी टकराव और सुरक्षा संबंधी किसी समस्या की आशंका न रहे। देव दीपावली की शाम गंगा के सभी प्रमुख घाटों पर दीपदान होगा। दशाश्वमेध घाट की विश्वप्रसिद्ध गंगा महाआरती आयोजन का आध्यात्मिक केंद्र होगी। नमो घाट, गायघाट, पंचगंगा, शीतला, केदार, तुलसी और अस्सी घाट सहित प्रमुख घाटों पर विशेष गंगा आरती की व्यवस्था की जा रही है। शंखनाद, वैदिक मंत्रोच्चार, घंटियों की गूंज और दीपों की कतारें काशी के धार्मिक वैभव को नया विस्तार देंगी।

पीएनबी ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर युवा कें